भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल
की
बैठक

दस्तावेज

1. कार्यसूची तथा कार्यक्रम
2. अध्यक्षीय संबोधन
3. महासचिव की रिपोर्ट
4. गतिविधियों की रिपोर्ट
5. 2012–13 की आय–व्यय का ब्यौरा
6. पत्रिकाओं की सर्कुलेशन

11–14 जुलाई, 2014

बेल्लारी, कर्नाटक

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

बेल्लारी कर्नाटक

11–14 जुलाई, 2014

कार्यक्रम

1 शोक प्रस्ताव
2 अध्यक्षीय भाषण
3 महासचिव की रिपोर्ट
4. चुनावों के बाद की स्थिति की समीक्षा और हमारे कार्य
5 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता का सत्यापन
6 प्रस्ताव
7 क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट
8 समापन भाषण

कार्यसूची

11 जुलाई 2014	
10.00 से 11.30 बजे	उद्घाटन सत्र झण्डारोहण तथा शहीद बेदी पर माल्यार्पण स्वागत भाषण, शोक प्रस्ताव अध्यक्षीय भाषण
12.00 से 01.30 बजे तक	जनरल कौंसिल की बैठक शोक प्रस्ताव महासचिव की रिपोर्ट
3.30 से 7.00 बजे तक	भ्रातृ प्रतिनिधियों के संदेश, प्रस्ताव महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
12 जुलाई 2014	
9.30 से 1.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
तथा 03.30 से 08.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
13 जुलाई 2014	
9.30 बजे से 1.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
तथा 3.30 बजे से 7.00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
07.00 बजे	सैक्रेटैरिएट की बैठक
14 जुलाई 2014	
9.30 बजे से 2.00 बजे तक	क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट बहस का जवाब, रिपोर्ट पारित करना, प्रस्ताव, समापन भाषण
5.00 बजे	रैली तथा जनसभा

(चाय के लिए अवकाशः दोपहर 11.30 से 12.00 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 5.30 बजे तक)
(भोंजनावकाशः दोपहर 1.30 बजे से शाम 3.30 बजे तक)

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)
जनरल कौंसिल की बैठक
बेल्लारी कर्नाटक

11–14 जुलाई, 2014

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय साथियों,

सीटू के सचिव मंडल की ओर से और अपनी ओर से मैं, हमारे 14वें सम्मेलन में कन्नूर में चुनी गई जनरल काउंसिल के सदस्यों और विशेष आमन्त्रितों का काउंसिल की इस पहली बैठक में स्वागत करता हूँ।

मैं इस अहम समय में इस बैठक के आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्वागत समिति और कर्नाटक राज्य समिति को भी हमारा अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।

अप्रैल 2013 में हमारे 14वें सम्मेलन के बाद वर्किंग कमेटी की बैठक 27–29 अगस्त तक जयपुर, राजस्थान में हुई। वर्किंग कमेटी और इस जनरल काउंसिल बैठक के बीच के अन्तराल में ऐसे दो साथियों का निधन हो गया जिन्होंने हमारे संगठन में अग्रणी भूमिका अदा की।

कॉ0 आर उमानाथ, हमारे प्यारे नेता का जिन्होंने सीटू की स्थापना करने में अग्रणी भूमिका निभाई, 21 मई को निधन हो गया। उन्होंने अपने करीब 70 वर्ष के सक्रिय सार्वजनिक जीवन में, सीटू के निमार्ण और विभिन्न ट्रेड यूनियनों का दिशा–निर्देशन करने में अहम भूमिका अदा की। उनकी स्मृति को श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनकी ओर से मुझे प्राप्त हुए व्यक्तिगत अवधान और दिशा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जो उनके साथ काम करने के दौरान मुझे मिला।

हमारे उपाध्यक्ष कॉ0 के एल बजाज ने 18 अप्रैल को अंतिम सांस ली। वे सीटू की स्थापना से ही विभिन्न हैसियतों में उसके साथ जुड़े रहे थे और मजदूर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध हमारे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। आइये, हम हमारे प्यारे कॉमरेड बजाज की याद को अपनी श्रृद्धांजलि दें।

इस अन्तराल में, देश में मजदूर वर्ग ने कुछ ऐसी अग्रणी शख्सियतों को खो दिया है जिनका उसकी बेहतरी के लिए संघर्ष में काफी योगदान था। मानवता ने कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को खोया है जिन्होंने रचनात्मक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता साबित की। हम उन सभी को अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं।

हम शहीदों को, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के उन शहीदों को अपनी श्रृद्धांजलि देते हैं जो सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेस व अन्य के गुण्डों द्वारा बर्बर हमलों का शिकार बने।

इस अवसर पर हम, लोगों के जनवादी हकों की हिफाजत करने में इन क्रूर हमलों का प्रतिरोध करने वालों का अभिवादन करते हैं।

हम, विभाजनकारी ताकतों के हमलों में, प्राकृतिक आपदाओं, कार्यस्थलों पर हुई और सड़क तथा रेल दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में गई जानों पर गहरे दुख का इजहार करते हैं।

साथियों,

हम, 16वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के समापन के दो महीने के भीतर मिल रहे हैं। हम सभी इस विशाल चुनावी प्रक्रिया के परिणामों से अवगत हैं जिसका नतीजा भारतीय राजनीति के दक्षिणपंथ की ओर और अधिक झुकाव के रूप में सामने आया है।

दस वर्षों तक देश पर शासन करने वाले यूपीए का बहुत से राज्यों में पूरी तरह सफाया हो गया। काँग्रेस से हुए अलगाव का फायदा भाजपा और एनडीए को मिला। भाजपा ने अकेले 282 सीटें प्राप्त कीं और एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है।

भारतीय कार्पोरेट्स और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के पूर्ण समर्थन के साथ सत्तारूढ़ हुई सरकार ने 'सुधारों' को तेज करने के अपने एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। आर एस एस जैसे संगठनों की परोक्ष–अपरोक्ष गतिविधियों ने भी भाजपा की जीत में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

इन चुनावों के परिणाम देश के मजदूर वर्ग के लिए एक गंभीर धक्का हैं। जनता के संघर्षों में हमेशा आगे रहने वाली वामपंथी पार्टियों को इन चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और लोकसभा में उनकी इतनी कम ताकत पहले कभी नहीं थी। तथापि, त्रिपुरा में दोनों ही सीटों पर वामपंथी दलों ने और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। हम त्रिपुरा के साथियों की उनकी शानदार जीत पर बधाई देते हैं। हम, केरल के साथियों का भी अभिवादन करते हैं जहाँ एल डी एफ ने पिछले चुनावों के मुकाबले दोगुनी सीटों पर जीत दर्ज की।

सीटू ने आम चुनावों से काफी पहले ही देश के मेहनतकश लोगों को इस खतरनाक परिणाम के बारे में सावधान किया था और हमारी यूनियनों व समितियों से जनता के बीच वामपंथी पार्टियों द्वारा सामने रखी गईं वैकल्पिक नीतियों को प्रचारित करने का आह्वान किया था। ये वही नीतियां थीं जिनपर हमारे सम्मेलनों और दस्तावेजों में हमने बराबर जोर दिया था। ये नीतियां ही संयुक्त ट्रेड यूनियन आन्दोलन के 10 सूत्रीय मांगपत्र का आधार थी, जिनपर कई सारे एतिहासिक संघर्ष हुए।

मुझे यकीन है कि जनरल काउंसिल की यह बैठक इन मुद्दों की तह तक जायेगी और इन चुनावों की प्रक्रिया में सामने आयी हमारी कमियों ओर कमजोरियों का समुचित आकलन करेगी। हमारे सामने मौजूद चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए हमें इन कमजोरियों को जल्द से जल्द दुरूस्त करना होगा।

यह भी गौरतलब है कि साझा मांगपत्र पर संघर्षों का संयुक्त रूप से नेतृत्व करने वाली सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने, मेहनतकश लोगों पर बढ़ते हमलों के इस दौर में संयुक्त आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है।

एनडीए के सत्तारूढ़ होने के कुछ ही दिन के भीतर जो संकेत मिले हैं वे अशुभ हैं। विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन करने के एकतरफा कदम, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी, रेल के यात्री व माल भाड़े में वृद्धि, सभी एनडीए सरकार की 'कड़े कदमों' की नीति की दिशा का संकेत देते हैं।

आने वाले दिनों में इन हमलों का मुकाबला करने के लिए सीटू को पूरी तरह तैयार होना होगा।

साथियों,

हमने अपने कन्नूर सम्मेलन में और फिर वर्किंग कमेटी की जयपुर बैठक में पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट के गंभीर प्रभावों को नोट किया था। यह संकट आज भी जारी है। आई एम एफ, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सभी रिपोर्ट्स संकट के गहरे असर की ओर इशारा करती हैं।

सबसे ताजातरीन रिपोर्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में है जो इस वर्ष की पहली तिमाही में 2.9% सिकुड़ गयी है। रिपोर्ट के अनुसार पाँच वर्षों में यह उसकी सबसे खराब स्थिति है। अमेरिका की इस स्थिति के लिए सार्वजनिक खर्च की कमी को एक सबसे प्रमुख कारण बताया गया है।

दुनिया, रोजगारों के जबर्दस्त नुकसान से उभर नहीं सकी है। बेरोजगारी और बढ़ती गैर–बराबरी, तथा विभिन्न देशों द्वारा अपनाये गये और अधिक मितव्ययिता के कदमों का परिणाम समूची 'विकसित दुनिया' में संघर्षों के रूप में सामने आया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी 'वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2014' में संकेत दिया है कि 'अगले पाँच वर्षों में अनुमानित 21 करोड़ 30 लाख नये लोग श्रम बाजार में प्रवेश करेंगे–जिनमें से 20 करोड़ अकेले विकासशील देशों में होंगे'। इस रिपोर्ट ने युवा बेरोजगारी को मौजूदा संकट की एक गंभीर देन के रूप में दर्ज किया है। यूरोप के कुछ देशों में युवा बेरोजगारी की दर 50% को पार कर गई है।

इसी रिपोर्ट में वर्तमान में काम कर रहे लोगों की नाजुक प्रकृति का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट नोट करती है कि विकासशील देशों में 83 करोड़ 90 लाख मजदूर इतना कमा पाने में असमर्थ हैं जितना उन्हें और उनके परिवारों को 2 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी की देहरी के पार ले जाने के लिए जरूरी है।'

इस वर्ष की रिपोर्ट में जहाँ आई एल ओ ने विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित किया है वहीं दूसरी विभिन्न रपटों में यूरोप की स्थिति का जिक्र किया गया है।

स्पेन, यूरोप के हालात का एक उदाहरण है जहाँ 2011 व 2013 के बीच बेरोजगारी की दर में 3.18% की वृद्धि हुई है, और जहाँ 6,73,900 स्थायी रोजगार खत्म हो चुके हैं। अंशकालिक कर्मियों से 'ओवरटाइम' काम लेते हुए अंशकालिक रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या जहाँ 2,56,600 से बढ़कर 24,24,100 हो गई है वहीं पूर्णकालिक रोजगार के करारों में 13,57,400 की कमी आयी है। स्पेन में युवा बेरोजगारी 56% पर पहुँच गई है। इस क्षेत्र में हर एक देश की कमोबेश एक जैसी स्थिति है लेकिन संकट का आयाम भिन्न है। प्रवास बराबर एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, रोजगार की तलाश में लाखों लोग अपना घर छोड़ बाहर जा रहे हैं और 'युद्ध क्षेत्रों' तक में काम करने को मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय लड़ाईयों के कारण हुआ प्रवास अभी तक का सबसे बड़ा प्रवास भी है, जिसे अब 5 करोड़ से ज्यादा आंका जा रहा है।

बढ़ती गैर–बराबरी

पिछले कुछ महीनों में, बढ़ती गैर–बराबरी का सवाल गंभीर चर्चाओं का बिन्दू बन गया है। यहाँ तक कि पोप फ्रांसिस द्वारा भी नियमित रूप से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। धन के संचय की और इशारा करते हुए एक महीना पहले ही उन्होंने कहा,–'हमने पैसे को केन्द्र में स्थापित कर दिया है, पैसे का भगवान। हम मूर्तिपूजा के पाप में फंस गये हैं; पैसे की पूजा।' उन्होने यह भी कहा कि, 'मैं सोचता हूँ कि हम एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हैं जो अच्छी नहीं है'।

एक धर्मगुरू के 120 करोड़ रोमन कैथोलिक्स के धार्मिक गुरू के जहाँ ये विचार हैं वहीं सारी दुनिया में अकादमिक मंचों पर 'बढ़ती असमानता' पर गंभीर चर्चायें हो रही हैं। यह पेरिस स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स के प्रोफेसर थामस पिकेट्टी के एक गंभीर अध्ययन – '21 वीं सदी में पूंजी' पर आधारित है। गैरबराबरी पर इस अध्ययन ने जो सामने रखा है उसे कुछ लोगों ने 'पिकेट्टीमेनिया' के तौर पर वर्णित किया है। मुख्यतः पिछले 200 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन कर उन्होंने अपने निष्कर्ष में कहा है कि एक 'भयंकर गैरबराबरी, मुक्त बाजार के पूंजीवाद का अवश्यमभावी परिणाम है'। उनका कहना है, 'यह विचार कि बेलगाम प्रतियोगिता उत्तराधिकार का अंत कर देगी और एक कहीं अधिक मेरिटोक्रेटिक विश्व की ओर आगे बढ़ेगी, एक खतरनाक भ्रम है'।

आई एम एफ के मुखिया क्रिसटाइन लागार्दे का कहना है – 'आज दुनिया में 10 में से 7 लोग उन देशों में रहते हैं जहाँ पिछले तीन दशकों में गैरबराबरी बढ़ी है। इसके साथ यदि हम एक दूसरे आंकड़े को रख कर देखें जो कहता है – 'दुनिया के सबसे धनी 85 लोगों के पास जितना धन है वह पूरी दुनिया की नीचे की आधी आबादी के कुल धन के बराबर है।'

हाल ही में किए गये ऐसे कई अध्ययन हैं जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों – ओ ई सी डी (आर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कोआपरेशन एंड डेवलपमेंट) के अधिकतर देश–धनी देशों का क्लब और ब्राजील, चीन व भारत जैसी कथित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इस वास्तविकता को उजागर करते हैं। भारत के बारे में ओ ई सी डी का एक अध्ययन कहता है 'कमाई के मामले में पिछले कुछ दशकों में भारत में गैरबराबरी दूनी हो गई है जो उसे सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे बुरी स्थिति में रखती है। भारत में वेतन आमदनी वाले सबसे ऊपर वाले 10% लोग अब सबसे निचले वाले 10% से 12 गुना ज्यादा आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। यह 1990 के दशक की शुरूआत के छः के अनुपात से कहीं ऊपर है'।

आई एम एफ के मुखिया का कहना है, 'भारत में, खरबपतियों के समुदाय की शुद्ध संपदा 15 वर्षों में 12 गुना बढ़ी है, जो इस देश से दो बार गरीबी का पूरा तरह उन्मूलन करने के लिए काफी है'।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि धन के इस अशिष्ट संचय के लिए आई एम एफ, विश्व बैंक आदि के नीति नुस्खे ही प्रमुख कारण हैं।

मजदूरों पर हमले

लातिनी अमेरिका की जनवादी सरकारों को छोड़कर, दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में विभिन्न सरकारें मेहनतकश लोगों के खिलाफ हमलावर रही हैं।

नीचे दी गई तालिका यह दर्शाती है कि यूरोपीय देशों में सार्वजनिक कर्मचारी कैसे हमलों के सामने रहे हैं:

वेतन कटौती, वेतन जाम का सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव

	वेतन कटौती	वेतन जाम	अन्य दबाव
बेल्जियम			वरिष्ठता एलवांसमेंट को बोनस के साथ प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव। 2009–2011 में केंद्र सरकार में रोजगार में 12 प्रतिशत कमी।

चेक गणतंत्र	वर्ष 2011 में 10 प्रतिशत वेतन कटौती	10 प्रतिशत वेतन कटौती 2014 तक	
डेनमार्क		2010 में वास्तविक मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं	2011 में वरिष्ठता बोनस लाभों की समाप्ति
जर्मनी		वर्ष 2012–14 के बीच 2 मिलियन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में केवल 6.3 प्रतिशत वृद्धि	
एस्टोनिया	मूल वेतन में 6 प्रतिशत कटौती; वर्ष 2008 से 2010 के बीच सार्वजनिक प्रशासन में बड़े पैमाने पर कटौती	2009 – 2010	परफॉर्मेंस संबंधित अनुपूरक हित लाभ व अन्य अतिरिक्त भुगतानों में कटौती /समाप्त किया जाना
आयरलैंड	कम से कम 5 प्रतिशत वेतन कटौती; नई भर्तियों के लिए 10 प्रतिशत वेतन कटौती		
ग्रीस	वेतन कटौती की श्रृंखला जारी, इसके आधार पर एक नया वेतन ढांचा	प्रतिमाह 2000 यूरो से अधिक कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन जाम (2009)	13वें व 14वें माह की वेतन कटौती व निष्कासन तथा नया वेतन ढांचा जिसके तहत कम से कम 15 – 20 प्रतिशत वेतन कटौती की गई। सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली में बदलाव व इसके बदले में प्रोत्साहन भुगतान प्रणाली को लागू किया जाना। 2011 में काम के घंटे प्रति सप्ताह 37.5 से बढ़ाकर 40 घंटे कर दिए गए। 2015 तक रोजगार में 150,000 (20 प्रतिशत) नियोजित कमी।
स्पेन	2010 में 5 प्रतिशत वेतन कटौती	2011 व 2012 में भी वेतन कटौती जारी	वर्ष 2012 में काम के घंटे प्रति सप्ताह 35 से बढ़ाकर 37.5 कर दिए गए और अध्यापकों के संपर्क समय में बढ़ोतरी कर दी गई।
फ्रांस		2 वर्ष के लिए वेतनमान जाम	सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी छोड़ने वाले दो व्यक्तियों के बदले एक की नियुक्ति
इटली	वर्ष 2011 – 13 में 90,000 यूरो से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के वेतन में 5 प्रतिशत कटौती, 150,000 यूरो से अधिक वेतन प्राप्त करने वालों में 10 प्रतिशत वेतन कटौती	वर्ष 2011 – 13 में वर्ष 2010 के स्तर पर वेतन जाम और 2014 में भी इसके जारी रहने की संभावना	2010 – 12 में सामूहिक सौदेबाजी समाप्त करना; कर्मचारियों की रगड़ाई; 2011 – 13 की अवधि में 5 के स्थान पर केवल एक कर्मचारी की नियुक्ति; 2014 के अंत तक यही स्थिति बने रहने की संभावना
साईप्रस	2011 में वेतन कटौती प्रस्तावित	3 वर्ष	

लताविया	2009 में 15 प्रतिशत वेतन कटौती; 2010 में उच्च वेतन पाने वालों के वेतन में 20 प्रतिशत कटौती व निम्न वेतन पाने वालों में 15 प्रतिशत कटौती		आईएमएफ के साथ समझौते के अनुसार : केंद्र व स्थानीय सरकारी संस्थानों में एकल वेतन प्रणाली की शुरुआत जिसके कारण वर्ष 2009 की तुलना में 2010 में वेतन में औसतन 5 प्रतिशत कटौती हुई।
लिथुआनिया	15 प्रतिशत कटौती	2012 तक	
हंगरी	7 प्रतिशत तक कटौती	2009 से वेतन जाम	सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों को 13वें माह के वेतन की समाप्ति (सालाना वेतन का 8 प्रतिशत) के बदले न्यूनतम दर पर भुगतान (2009 / 10)। 2012 में सरकारी नौकरियों में 7000 की कटौती की घोषणा
नीदरलैंड		केंद्र सरकार के तहत 2011 से कोई वेतन समझौता नहीं — वेतन जाम	2012 में एलआईएफओ नियम के समाप्त होने से केंद्र सरकारी कर्मचारियों को निष्कासित करना आसान जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा 2015 तक रोजगार में कमी
पोलैंड		दो वर्ष के लिए वेतन जाम	वेतन जाम से अध्यापकों को अलग किया गया (व इनके वेतन में वृद्धि हुई)
पुर्तगाल	2011 में 5 प्रतिशत वेतन कटौती; संवैधानिक न्यायालय में चुनौती के बावजूद 2012 में मध्यम व उच्च वेतन पाने वालों के 13वें व 14वें माह के वेतन निलंबित	2011 से 2013 तक दो साल तक वेतन जाम	स्वास्थ्य लाभों में कटौती
रोमानिया	2010 में 25 प्रतिशत अस्थाई कटौती, नई वेतन प्रणाली में आंशिक बहाली की गई।	2012 तक जारी	2012 में नई वेतन प्रणाली की शुरुआत से बोनस राशि की सीमा समाप्त व 13वें माह के वेतन की समाप्ति
स्लोवेनिया	2011 में 4 प्रतिशत वेतन कटौती; 2012 में औसतन 8 प्रतिशत अतिरिक्त कटौती	2011 व 2012 (छः माह) तक	
स्लोवाकिया	2011 में 10 प्रतिशत वेतन बिल में कटौती		अध्यापक व कुछ अन्य समूह वेतन कटौती से प्रभावित नहीं
स्वीडन		वेतन में कोई बदलाव नहीं	कांट्रैक्ट के तहत तय अवधि के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ में कटौती
यू0 के0	प्रीमीयम भुगतानों व भत्ते में कटौती (विशेष तौर पर स्थानीय सरकारी कर्मचारियों में)	2010 — 2012 में कुछ न्यूनतम वेतन पाने वालों को छोड़कर शेष सभी के प्रीमीयम भुगतानों व भत्ते में कटौती	2013 — 14 की योजना के तहत वेतन वृद्धि पर 1 प्रतिशत की सीमा लगाई गई, 2010 — 15 के बीच रोजगार में बड़े पैमाने पर 10 प्रतिशत से अधिक कटौती की योजना

इसकी तुलना सी ई ओ और ऊंचे ओहदेदारों को मिल रहे विशाल 'कम्पेन्सेशन' से कीजिये। फ्रांस में जहाँ वेतन फ्रीज और कटौतियों के लागू रहते औसत वेतन 25,500 यूरो सालाना है वहीं फ्रांस में सी ई ओ का 'कम्पेन्सेशन' 20% से 37% की वृद्धि के साथ 34 लाख और 37 लाख यूरो पर पहुंच गया। इटली में टेलीकॉम इटालिया के सी ई ओ को 82 लाख यूरो मिलते हैं। विभिन्न देशों में आय में असमानतायें बढ़ रही हैं।

अमेरिका में भी 1970 के दशक के बाद मजदूरों के वास्तविक वेतन में वस्तुतः ठहराव है। आय में असमानतायें भी बढ़ रही हैं। सबसे ऊपर वाले 1% की आय 165% बढ़ी है और सबसे ऊपर के 0.1% की 362%। 99 फीसदी और 1 फीसदी का तुलनात्मक अन्तर दरअसल 99.9% बनाम 0.1% में बदल गया है।

आज, समूचे विकसित विश्व में मेहनतकश लोग न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में यूरोप और अमेरिका में भी हड़तालों समेत बड़े संघर्ष हुए हैं।
मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर एक तीखा हमला है। सामूहिक समझौतों की संख्या में कमी आ रही है। स्पेन में 2007 में 6016 समझौतों पर दस्तखत हुए जो 2011 में घटकर 4585 और 2013 में 2094 रह गये। 2014 की पहली तिमाही में सिर्फ 571 समझौते हुए है। संकट से पहले समझौतों के दायरे में आने वाले मजदूरों की संख्या 10 करोड़ 20 लाख थी लेकिन आज यह मात्र 27 लाख हैं। एक ऐसा नियम था कि यदि नये समझौते पर नहीं पहुँचा जाता है तो उस वक्त तक जारी समझौता तब तक कायम रहेगा जब तक नये पर दस्तखत नहीं हो जाते हैं। अब इसे एक वर्ष तक सीमित कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस समय सीमा के बाद मौजूदा फायदों को भी नकारा जा सकता है।

स्पेन में, नियोक्ताओं के संगठन के अनुसार 2014 के पहले दो महीनों में 184 हड़तालें हुईं जिनमें 56,693 मजदूर शामिल हुए। 2013 में हुईं 1259 हड़तालों में 5 लाख से ज्यादा मज़दूरों ने भाग लिया था।

15 मई 2014 को फ्रांस में हुई एक दिन की हड़ताल में 55 लाख कर्मचारियों ने हिस्सेदारी की इससे हवाई यातायात समेत यातायात सेवाओं और सरकारी कार्यालयों कीं स्थिति अस्त–व्यस्त हो गई। मजदूर अपने रोज़गार की शर्तों पर हमलों का विरोध कर रहे थे।

इटली में शिक्षकों और सामाजिक कामगारों समेत हजारों मयूनिसिपल वर्कर्स, कमखर्ची अभियान के तौर पर 200 यूरो (271 डॉलर) प्रतिमाह की प्रस्तावित वेतन कटौती के खिलाफ हड़ताल पर गये।

अमेरिका में, न्यूनतम वेतन को 15 डॉलर तक बढ़ाये जाने का संघर्ष जोर पकड़ रहा है। सिएटल, अमेरिका में मजदूर वर्ग, संयुक्त अभियान और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के माध्यम से 15 डॉलर प्रति घंटे की मांग को हासिल कर सकने में सफल हुआ है। ऐसा अनूमान है कि इससे 25% मेहनतकश गरीब उस दर्जे से ऊपर उठ सकेंगे। ओ ई सी डी के आंकड़ों के मुताबिक एक अमेरिकी कामगार औसतन, एक कनाडियन कामगार के मुकाबले 4.6%, एक फ्रांसीसी कामगार के मुकाबले 21% और एक जर्मन कामगार के मुकाबले 28% ज्यादा घंटो तक खपता है।

जाने–माने नोबल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्तिगलित्ज का कहना है, 'अमेरिका न केवल गैरबराबरी के सबसे ऊंचे स्तर के साथ विकसित देश बना है बल्कि वह एक ऐसा देश है जहाँ अवसर की समानता सबसे कम है'। केवल यूरोप और अमेरिका ही नहीं, अन्य महाद्वीपों में विभिन्न देशों में, भी हड़तालें और संघर्ष हो रहे हैं।

इस दौरान लम्बी चली एक अहम हड़ताल, पाँच महीने लम्बी दक्षिण अफ्रीका के प्लेटिनम खनिकों की हड़ताल रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्लेटिनम खदानों में हुई इस हड़ताल ने हाल ही में हुए दक्षिण अफ्रीका के चुनावों में एक राजनीतिक

मुद्दा बनने के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। इसे दक्षिण अफ्रीका में खनिकों की सबसे लंबी हड़ताल बताया गया है।

मजदूर, 25 जून को हुए वेतन समझौते के बाद काम पर लौट आये। इससे उन मजदूरों को, जिनकी बेसिक सेलरी 12500 रैंड से कम है, पहले दो वर्ष में 1000 रैंड (95 डॉलर) की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 950 रैंड की वृद्धि मिलेगी। कंपनियों ने अपना कुल जमा नुकसान 24 अरब रैंड (2.27 अरब डॉलर) बताया और मजदूरों के वेतन नुकसान को 10.6 अरब रैंड आंका गया।

ब्राजील में वहाँ चल रहे फुटबॉल विश्व कप 2014 और 2016 में वहाँ होने वाले ओलिम्पिक खेलों पर विशाल खर्च के खिलाफ एक के बाद एक लगातार आंदोलन हुए हैं। यह सब इसके बावजूद हुआ है कि ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ फुटबॉल को जीवन के एक तरीके के रूप में पसंद किया जाता है!

कुछ अहम राजनीतिक घटनायें

मैं राजनीतिक घटनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ।

साम्राज्यवाद, विश्व के हर हिस्से में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हुए है।

आतंकवाद के खिलाफ तथाकथित युद्ध और सम्प्रभु देशों में परोक्ष–अपरोक्ष हमलों के परिणामों का हम अनुभव कर रहे हैं। एक संकीर्णतावादी जंग बरपा कर जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतों द्वारा इराक पर शिकंजा कसा जा रहा है वह अमेरिका–ब्रिटेन के आक्रमणों का नतीजा है। सीरिया के एक बड़े हिस्से पर भी आज इन्हीं ताकतों का कब्जा है। लेकिन, अभी तक सीरियाई सरकार का देश के प्रशासन पर नियन्त्रण है। अफगानिस्तान, यमन और यहाँ तक कि पाकिस्तान की स्थिति भी साम्राज्यवादी दखल का नतीजा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा एक देश के खिलाफ दूसरे को खड़ा करने और सभी अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों के उल्लंघन ने ऐसी परिस्थिति पैदा की है।

इराकः इराक से नरसंहार की कंपा देने वाली रिपोर्ट आ रही हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आई एस आई एस) के आतंकियों द्वारा सैंकड़ो नागरिकों को वीभत्स तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है। आई एस आई एस एक ऐसी इकाई है जिसे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने के लिए अमेरिका ने पैदा किया है, उसे पैसा और हथियार दिये हैं। आई एस आई एस का घोषित लक्ष्य सीरिया (और इराक) में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना और इस्लामिक खलीफा की वापसी करना है, जो 1924 में ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद समाप्त हो गया था। दुनिया को अचम्भित करने वाले एक हमले में आई एस आई एस के आतंकियों ने इराकी भू–भाग के बड़े हिस्सों में तबाही मचा दी और इराक के दूसरे सबसे अहम शहर मोसुल पर कब्जा कर लिया। बगदाद से 100 किलोमीटर से भी कम के फासले पर वे इराकी सैन्य बलों और हिफाजत के लिए हथियार उठाने के आह्वान पर उनके साथ शामिल शिया नागरिकों के साथ जबर्दस्त लड़ाई में उलझे हुए हैं।

अमेरिका इस लड़ाई में पूरी तरह शामिल होने के लिए भले ही अपनी फौज इराक में भेजे या न भेजे यह नोट किया जाना चाहिये कि इस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह सब अमेरिकी हितों के पोषण के लिए ही हो रहा है। विभिन्न देशों में हमलों और उनके अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी के पीछे उसके रणनीतिक हित काम कर रहे होते हैं। इराक, सीरिया और लीबिया जैसे इस क्षेत्र के धर्मनिरपेक्ष राज्यों को छिन्न–भिन्न कर संकीर्णतावादी दुश्मनी को हवा दी गयी जिससे इन राज्यों के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका इस क्षेत्र और उसके संसाधनों पर अपना एकछत्र प्रभुत्व स्थापित करने के लिए

इस क्षेत्र में कमजोर राज्य चाहता है। अमेरिका ने हमेशा ही 'पूर्व सोवियत संघ' में अपने प्रभाव के विस्तार के लिए पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अपने 'पैर टिकाने की जगहों' के तौर पर देखा है। अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले और पाकिस्तान में उसकी दखलअंदाजी ने किस तरह इन देशों को बर्बाद किया है यह सर्वविदित है। यूक्रेन तक में 'रचनात्मक अफरा–तफरी' की मुहिम से जो संकेत मिल रहे हैं वे वास्तव में अशुभ हैं।

मिश्रः राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी की चनी हुई सरकार के खिलाफ तख्तापलट के बाद फौजी जनरल आधिकारिक रूप से देश का राष्ट्रपति बन गया है। चुनावों के बाद फौजी जनरल के नेतृत्व वाली सरकार का मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ हमला जारी है और इन हमलों को दूसरे विभिन्न जनवादी तबकों तक बढ़ाया जा रहा है फौज ने तख्ता पलट के लिए ब्रदरहुड सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का इस्तेमाल किया और अब हालात वापस मुबारक सरकार के समय में लौट आये हैं। मेहनतकश लोगों और जनवादी तबकों के लिए पतिरिस्थितियां घूम कर फिर वहीं आ गई हैं।

यूक्रेनः लोगों के एक हिस्से की अपने देश को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाने की चाहत के चलते, यूक्रेन में, हाल के दौर में संकीर्णतावाली विरोध के कुछ सबसे बुरे रूप सामने आये हैं। इन लोगों के पीछे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ताकतों का सक्रिय हाथ है क्योंकि वे नाटो के प्रभाव को रूस की सीमाओं तक फैलाना चाहते हैं जिसने इसे एक खतरे के रूप में देखा है और इसका विरोध किया है। यूरोपियन यूनियन के पक्ष में हुए विरोध में नव–फासीवादी समूहों ने घुसपैठ कर यूक्रेन में रह रहे रूसियों के एक बड़े हिस्से को निशाना बनाया। निर्वाचित राष्ट्रपति का तख्तापलट कर दिया गया और वह शरण लेने के लिए रूस भाग गया । कम्युनिस्टों और ट्रेड यूनियनों पर हमले किये गये और उनके दफ्तरों को जला दिया गया। रूस ने क्रीमिया में अपनी फौजें भेजीं जहाँ काला सागर में उसका नौसैनिक बेड़ा तैनात है। क्षेत्र में रहने वाली बहुसंख्यक रूसी आबादी ने एक जनमत संग्रह के जरिये यूक्रेन से अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और रूस के साथ मिलने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद हुए घटनाचक्र में देश के पूर्वी इलाके में रूसियों पर अमेरिका समर्थित हिंसक हमले हए। देश अब दरअसल एक गृहयुद्ध के बीच है जिसमें नव–फासीवादियों ने देश में एक आतंक राज बरपा किया हुआ है। हाल ही में एक अत्यंत कम हिस्सेदारी वाले चुनाव में देश ने एक नये राष्ट्रपति को चुना है जिसे यूरोपियन यूनियन के समर्थक के तौर पर जाना जाता है। रूस ने गैस की कीमतों पर विवाद को कारण बताते हुए यूक्रेन को गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। ताजा रपटों से संकेत मिला है कि यूक्रेन की सरकार ने रूस के साथ बातचीत की पेशकेश की है।

लैटिन अमेरिकी देशः अमेरिकी साम्राज्यवाद की अपरोक्ष कारगुजारियों के चलते वेनेजुएला खासतौर पर गंभीर दिक्कतों के दौर से गुजर रहा है। जहाँ भड़काऊ गतिविधियां जारी हैं वहीं मदूरो सरकार ने हूगों शावेज की जनहितैषी नीतियों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। लातिनी अमरीका के अन्य देशों में भी जन–हितैषी लोकतांत्रिक सरकारें कई बाधाओं का सामना कर रही हैं लेकिन वे एकजुट होकर आगे बढ़ रही हैं।

यूरोपियन यूनियन के चुनावः गहराते आर्थिक संकट और मेहनतकश जनता की बढ़ती मुश्किलों की पृष्ठभूमि में, यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनावों के नतीजे गौर करने वाले हैं। यूरोपियन मतदाताओं ने यूरासेपटिक और मितव्ययता विरोधी पार्टियों को लाखों नये वोट दिये। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के 751 सदस्यों को चुनने के लिए हुए इन चुनावों में मतदान करने वालों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखने में आयी। ई पी पी (यूरोपियन पीपुल्स पार्टी – मुख्यतः क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के घटकों का एक कंजरवेटिव समूह) ने 28.40 प्रतिशत मतों के साथ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की 214 सीटें जीतीं। 2009 में उसे 35.77 प्रतिशत वोट और 274 सीटें मिली थीं। हसी तरह प्रोग्रेसिव एलायंस ऑफ सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स के एस एंड डी समूह ने 25.43 फीसद मतों के साथ 191 सीटें जीती हैं। 2009 में उसे 25.59 फीसदी मत और 196 सीटें मिली थीं। कम्युनिस्ट पार्टियों व अन्य लेफ्ट/ग्रीन पार्टियों के जी यू ई/एन जी एल (यूरोपियन यूनाइटेट लेफ्ट/नोर्डिक ग्रीन लेफ्ट) समूह अपने सदस्य सांसदों और मत प्रतिशत को 2009 की क्रमशः 35 सदस्यों की संख्या और 4.57 प्रतिशत मतों को 45 सदस्य सांसदों और 5.99 प्रतिशत मतों तक बढ़ा लिया। दक्षिणपंथी दलों को भी विदेशियों के प्रति घृणा या द्वेष की

मारक नीतियों के समथकों के वोटों की भारी संख्या पर हाथ–साफ करने में सफलता मिली। इन चुनावों के परिणाम के कारण स्पष्ट हैं। मतदाताओं ने अपने देशों के संप्रभु मामलों में यूरोपीय आयोग के हस्तक्षेप के खिलाफ यह वोट दिया है। यह वोट उनकी अपनी राष्ट्रीय सरकारों के खिलाफ दिया गया वोट भी है जो यूरोपियन यूनियन के सुझाये कमखर्ची के कदमों को आगे बढ़ा रही हैं। यह, लोगों की आजीविकाओं पर हमले की मुहिम, सम्पदा के निजीकरण, विभिन्न कल्याणकारी कदमों में कटौती और टैक्सों के बढ़ाये जाने के खिलाफ लोगों के गुस्से का इजहार है। यह वोट बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ क्रोध ा का इजहार भी है जो आज समूचे महाद्वीप में 1 करोड़ 90 लाख के ऊपर पहुंच गई है। यह, यूरोपियन यूनियन और विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों द्वारा, चाहे वे सोशल डेमोक्रेट्स की हों या कंजरवेटिव्स की, जनता के ऊपर कार्पोरेशंस को तरजीह दिये जाने के खिलाफ वोट है। धुर–दक्षिणपंथी पार्टियों ने, जिन्होंने इन चुनावों में अपनी स्थिति में सुधार किया है, मौजूदा बदतर हालात के लिए जिम्मेदार नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों की खिलाफत नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने अप्रवासियों खासतौर पर रोमा और मुसलमानों को बेरोजगारी और रोजगार छिनने का कारण मानते हुए, उन पर निशाना साधा है। उन्होंने खुलेआम नस्ली घृणा और 'राष्ट्रीय समाजवाद' के प्रति अपने मजबूत लगाव के, हिटलर के दर्शन की वकालत की है।

पड़ौसी देशः पाकिस्तान बराबर आतंकी समूहों के खतरे के साये में बना हुआ है। हवाई अड्डों समेत सरकारी प्रतिष्ठानों पर हाल ही में हुए हमलों से स्थिति की गंभीरता का पता चलता है।

बांग्लादेश भी एक नाजुक स्थिति का सामना कर रहा है। वहाँ हुए आम चुनावों का विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार किया गया। आवामी लीग की सरकार सत्ता में बनी हुई है। कट्टपंथी जमात–ए–इस्लामी और विपक्षी बी एन पी, सरकार के खिलाफ मिलकर काम कर रही हैं।

नेपाल में, हालिया चुनावों के बाद भी, संविधान सभा का कामकाज, इस मुद्दे पर, कि चुनावों में गड़बड़ी की जाँच के लिए आयोग का नेतृत्व कौन करेगा, गतिरोध का शिकार बना हुआ है। निकट भविष्य में एक जनवादी संविधान की सभी उम्मीदें हवा होती जा रही हैं।

श्रीलंका में, तमिल भाषियों के लिए समान अधिकारों, सत्ता के विकेन्द्री करण और नागरिकों के जनसंहार की जांच के मुद्दों का हल लगातार लटका हुआ है। हाल ही में बुद्धिस्ट अतिवादी संगठनों के द्वारा श्रीलंका में मुसलमानों पर हमले और उनकी हत्याओं ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। मछली पकड़ने को लेकर भारत ओर श्रीलंका के बीच विवाद भी जारी है और दोनों ओर वर्क्र्स कैद में बने हुए हैं।

यह गौरतलब है कि इन सभी पड़ोसी देशों में कट्टरंथी ताकतें और साम्राज्यवादी एजेंसियां भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इनमे हो रही कारगुजारियों में शामिल हैं। हमें, लगातार इस बात पर जोर देते रहना चाहिये कि हमारी सरकार को पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की जरूरत है।

साथियों,

मोदी सरकार के, एक ऐसी सरकार के चलते जो आर एस एस के आदेशों के अधीन होने के साथ ही भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के निर्देशों के मुताबिक नव–उदारवादी नीतियों पर और भी तेज अमल के लिए प्रतिबद्ध है, देश के मजदूर वर्ग को गंभीर हमलों का सामना करना तय है चूंकि सरकार पर चुनावों में मदद और समर्थन करने वालों को 'अदायगी' करने का दबाव होगा इसलिए मेहनतकश जनता के हर तबके पर हमला होगा।

जब सरकार श्रम कानूनों को, रोजगार पैदा करने में एक बाधा के रूप में देख रही है और तमाम श्रमिक अधिकारों को छीना जा रहा है तब हमें मजदूरों के सभी तबकों को संघर्ष में लामबंद करने के लिए तैयार होना होगा।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें न केवल साझा चार्टर पर एकजुट हैं बल्कि श्रम कानूनों में संसोधन के खिलाफ़ और कई दूसरे नीतिगत मुद्दों पर भी वे एक साथ हैं।

जो एकता वित्तमंत्री के साथ बजट पूर्व परामर्श में और 24 जून को नये श्रम मंत्री के साथ बैठक में दिखाई गई है उसे और मजबूत करना होगा।

जैसा कि हम अपने सम्मेलनों में जोर देते रहे हैं, सीटू को, इस संदेश को जमीनी स्तर तक ले जाना होगा और वहाँ एकता और कार्रवाईयों का निर्माण करना होगा।

इस समय विभिन्न विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हो रही हैं और हमें मेहनतकश जनता और जनता के व्यापक हिस्सों की एकता को तोड़ने और उसे नुकसान पहुँचाने की विभिन्न तिकड़मों का प्रभावी रूप से मुकाबला करना होगा। साम्प्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष को, नव–उदारवादी हमलों के खिलाफ संघर्ष से अलग रखकर नहीं चलाया जा सकता है। इन संघर्षों को एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ना होगाा कि मेहनतकशों और अन्य कमजोर तबकों को इन मुद्दों के बारे में शिक्षित और एकजुट किया जा सके।

सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दों पर हमारे हस्तक्षेपों को और प्रंभावी तथा सटीक बनाना होगा। ट्रेड यूनियनों को महिलाओं के ऊपर बर्बर हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी । देश का कोई हिस्सा, महिलाओं के खिलाफ ऐसे वीभत्स हमलों से अछूता नहीं है।

साथियों,

कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनायें हमारे समक्ष एक गंभीर मुद्दा बनी हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में हजारों जानें गई हैं। इन दुर्घटनाओं और पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे को हमारे द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सड़क और रेल दुर्घटनायें भी हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है।

प्रिय साथियों,

किसी भी और चीज से ज्यादा हमें इस तथ्य का संज्ञान लेना होगा कि जनता में नव–उदारवाद के फैसले के गंभीर असर और मजदूर वर्ग में विचारधारात्मक समझदारी के कमजोर होने के चलते हमें अत्यधिक सक्रिय होना होगा। यह समय हमें हर स्तर पर हमारी कार्यप्रणाली और अन्य संबंधित मुद्दों पर आत्मपरीक्षण करने का है। हमारे संगठन की वर्गीय उन्मुखता को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयासों की जरूरत हैं। आज की परिस्थिति गंभीर आत्मनिरीक्षण के साथ ही प्रभावी हस्तक्षेपों की भी माँग करती है।

मुझे यकीन है कि जनरल कौंसिल का विचार–विमर्श हमारी कमजोरियों को दुरूस्त करने का रास्ता तैयार करेगा। आइये हम 14वें सम्मेलन में तय किये गये 'जिन तक नहीं पहुँचे हैं उन तक पहुँचों' और 'वर्ग संघर्ष को तेज करो' के कार्यभार पर पुनः जोर दें।

साथियों,

मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूंगा यदि मैं आपको डब्ल्यू एफ टी यू के द्वारा उसके स्थापना दिवस को बेरोजगारी के खिलाफ कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने के आह्वान का स्मरण नहीं कराता हूँ।

दुनिया के हर एक देश में मेहनतकशों के हर तबके के लिए यह एक अत्यंत महत्व का मुद्दा है। आइये, हम पूरी दुनिया के अपने बहनों और भाइयों के साथ 3 अक्टूबर को बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए आवाज बुलंद करें।

अपने संबोधन का समापन करने से पहले, मैं एक बार फिर आप सभी को मेरा अभिवादन और स्वागत समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

सीटू जिन्दाबाद
मजदूर वर्ग की एकता जिन्दाबाद
एकता और संघर्ष की ओर आगे बढ़ें

ए के पद्मनाभन
अध्यक्ष

****

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

बेल्लारी कर्नाटक

11–14 जुलाई, 2014

महासचिव की रिपोर्ट

सीटू की यह जनरल कौंसिल मीटिंग जयपुर में हुई कार्य समिति की मीटिंग के लगभग 8 माह के बाद हो रही है। सर्वप्रथम हम मजदूर वर्ग के महान नेता और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, का० आर. उमानाथ को हार्दिक श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका 93 वर्ष की आयु में 21 मई 2014 को निधन हो गया। का० आर. उमानाथ ने आजीवन एक क्रान्तिकारी का जीवन जिया और उनके पूरे जीवन को इस देश और आम आदमी के लिए संघर्ष और कुर्बानियों की व्याख्या कहा जा सकता है। का० आर. उमानाथ हम सभी के लिए हमेशा ही प्रेरणा स्रोत बने रहेगें।

सीटू के उपाध्यक्ष का० के.एल. बजाज का निधन 18 अप्रैल 2014 को मुम्बई में हो गया। वह सीटू और देश के मजदूर आन्दोलन के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। हम उन्हें श्रृद्धांजलि देते हैं।

हम पश्चिम बंगाल के उन सभी बहादुर कामरेड़ों और समर्थकों को लाल सलाम करते हैं, जो 16वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान तृणमूल कॉंग्रेस के गुण्डों द्वारा पुलिस और नागरिक प्रशासन की मदद से की गयी हिंसा का शिकार हुए हैं, और उनकी यह हिसंक मुहिम आज तक भी लगातार जारी है।

पिछले दौर में देश और दुनिया की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक स्थिति में भारी बदलाव हुआ है। यह मजदूरों और मजदूर वर्ग के आन्दोलन पर सीधा–सीधा हमला है। इस स्थिति एवं उसमें मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के मामले में सीटू और सम्पूर्ण मजदूर आन्दोलन की भूमिका का विश्लेषण और पुननिरीक्षण इस जनरल कौंसिल मीटिंग में करना ही होगा। इस स्थिति के द्वारा पैदा की गयी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और अपनी राजनैतिक, विचारधारात्मक व सांगठनिक समझदारी और लक्ष्य एवं कार्य तय करने के वास्ते अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानना ही होगा।

अध्यक्षीय भाषण में अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के चलते अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी ताकतें अधिकाधिक आक्रामक तरीके से, अनेक देशों, विशेष रुप से विकासशील देशों के स्वतंत्र अधिकारों के मामले में दखलन्दाजी कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी और वैश्विक नैगमिक गठजोड़ द्वारा, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को काबू करके अपने हितों के लिए भारी वित्तीय पूँजी और अपने काबू के हर हथियार और तौर तरीकों को इस्तेमाल करते हुए उन देशों के नीति निर्माताओं को प्रभावित किया जा रहा है। साम्राज्यवादी एवं बहुराष्ट्रीय निगमों के इस आक्रामक तौर तरीके ने हमारे देश की स्थिति पर भी भारी असर डाला है।

1. राष्ट्रीय स्थिति

1.1.1 अगस्त 2013 को जयपुर में सम्पन्न हुई कार्यसमिति की मीटिंग के दौरान हमने 16वीं लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर, देश और मेहनतकशों के समक्ष उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वामपन्थ को मजबूत करने के लिए सीटू एवं मजदूर

आन्दोलन के दायित्व के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की थी। इसमें मेहनतकशों का आव्हान् किया गया था कि काँग्रेस और भाजपा दोनों के गठबन्धनों को हराऐं। सीटू ने पं० बंगाल में तृणमूल काँग्रेस जैसी फासीवादी ताकत के विरुद्ध और वामपन्थी उम्मीदवारों के पक्ष में काम करने का आव्हान् किया था।

1.1.2 लेकिन 16वीं लोकसभा के चुनावों के परिणामों से यह सिद्ध होता है कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को प्रभावी रुप से निभा नहीं पाए, यद्यपि इन घातक परिणामों के पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं। जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं वह कुल मिलाकर बहुत ही अनिष्टकारी स्थिति है। इन चुनाव परिणामों से जहाँ एक ओर सिर्फ 31 प्रतिशत वोट पाकर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को अगले 5 वर्ष देश पर शासन करने का बहुमत मिला है, तो दूसरी ओर लोकसभा में 12 सांसदों के साथ वामपन्थ की पहली बार इतनी कमजोर स्थिति हुई है। इस प्रकार दक्षिणपन्थ ने देश की सत्ता सभांल ली है। इसके कारण आम आदमी विशेष रुप से मेहनतकशों की जिन्दगी और जीविका पर भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसकी राजनैतिक और सामाजिक जटिलता बहुत ही घातक एवं चिन्ताजनक होने वाली हैं।

1.1.3 पूरे देश में वामपन्थ को भारी धक्का लगा है। त्रिपुरा, केरल और प० बंगाल को छोड़कर न सिर्फ अन्यत्र कहीं कोई सीट नहीं मिली है बल्कि 2009 के मुकाबले सभी राज्यों में वोट में भी भारी कमी आयी है। सिर्फ त्रिपुरा में ही वोट का हिस्सा बढ़ा है। केरल में वामपन्थ कुछ सीट और भी बढता सकता था परन्तु वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सका। इसके अलावा खतरनाक बात यह है कि राज्य में भाजपा की वोट हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। वामपन्थ को अपने सबसे मजबूत गढ़ प० बंगाल में 2011 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले कहीं अधिक बड़ा झटका लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 34 माह के दौरान, वामपन्थी पार्टियों उसके समर्थकों, ट्रेड़ यूनियनों और जनसंगठनों पर तृणमूल काँग्रेस के गुण्ड़ों और राज्य प्रशासन के भारी हमलों ने भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य में बहुत सारे स्थानों पर बूथों पर कब्जे और भारी हेराफेरी की घटनाओं की शिकायतें मिली हैं। राज्य में वामपन्थ के परम्परागत मजबूत गढ़ और मजदूरों के बीच भी जन समर्थन में आयी भारी कमी और भाजपा के वोट में हुई भारी वृद्धि से भी भारी झटका लगा है।

1.1.4 इस सम्बन्ध में सीटू और मेहनतकशों के आन्दोलन के लिए तय किए गए अपने दायित्व के बारे में हमें गम्भीरता से विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण करने की सख्त जरुरत है। जनरल कौंसिल को आत्मालोचनात्मक तरीके से अपने काम की समाक्षा करनी होगी।

1.1.5 चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि 5 को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काँग्रेस विरोधी लहर का फायदा भाजपा और उसके गठबन्धन ने उठाया है। इन राज्यों में मजदूरों और कर्मचारियों सहित बहुत सी जनता को ऐसा लगा है कि उनकी जीविका सम्बन्धी समस्याओं का समाधान मोदी के नेतृत्व वाली सरकार प्रभावी तरीके से निकालेगी। ऐसा इस तथ्य के बावजूद भी है कि भाजपा भी उन्ही नीतियों का प्रचार करती है। भाजपा और अन्य वाम विरोधी ताकतें चुनावों के दौरान अपनी नीतियों पर पर्दा डालने में तथा वर्ग विभेद की नीतियों को बड़े पैमाने पर छुपाते हुए, विकास का मॉडल समझाने में सफल रहे हैं। वे जनता को यह समझाने में सफल रहे हैं कि विकास के लिए जिन नीतियों की वे बात कर रहे हैं, वह उनकी निगमों की समर्थक एवं बड़े व्यापारिक घरानों की समर्थक नीतियों से भिन्न है और जनता की समस्याऐं और अर्थव्यवस्था की समस्याओं का हल मोदी के नेतृत्व में "एक मजबूत और अच्छी सरकार" कर सकती है। उनके गैर–राजनैतिक विकास के मॉडल का सपना दिखाना जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, जिसका मुकाबला हम कहीं भी नहीं कर पाऐ हैं।

1.1.6 काँग्रेस के विरुद्ध उमड़ते गुस्से को देखते हुए देशी–विदेशी नैगमिक वर्गों (पूँजीपतियों) ने अपना पूरा ध्यान भाजपा की ओर मोड़ दिया। नैगमिक नियंत्रित संचार माध्यमों ने देश भर में मोदी लहर पैदा करने के लिए रात–दिन एक कर दिया। जनता को अपनी पसन्द चुनने को सीमित करने के लिए, कुछ एक बुद्धि जीवियों के द्वारा भी, चुनावों को कुछ इस प्रकार से पेश करने का बहुत ही संगठित प्रयास किया गया जैसे यह चुनावी संघर्ष सिर्फ मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा के तथा

राहुल गांधी के नेतृत्व वाले काँग्रेसी गठबन्धन के बीच ही है। महँगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आदि के लिए जिम्मेदार नीतियों पर बहस से बचने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया। इसके साथ ही साथ अभूतपूर्व तरीके से धन बल के उपयोग ने भी चुनावी परिणामों को बहुत अधिक प्रभावित किया है।

1.1.7 इसे महँगाई, बेराजगारी, श्रमिकों के दमन और राष्ट्रीय सम्पत्तियों को नीजी हाथों में सौंपने जैसी नव उदारवादी लूट के विरुद्ध खड़े होने वाले हर एक प्रतिरोध को कुचलने के लिए तथा नैगमिक वर्ग के प्रति पूरी तरह से वफादार निजाम खड़ा करने का यह सोचा समझा प्रयास कहा जा सकता है। वामपन्थ को सीमति करना भी नैगमिक वर्गों के इस प्रयास का अभिन्न हिस्सा रहा है। पूँजीपति वर्ग द्वारा अपने संकट से निकलने की रणनीति का यह आक्रामक एवं इरादतन राजनैतिक कूटनीति को ही दर्शाता है।

1.2 सीटू का चुनाव पूर्व आकलन

1.2.1 काँग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार की गलत नीतियों और कुशासन के कारण जनता से बढ़ते विलगाव को सीटू ने रेखांकित किया था। लगातार बढ़ती महँगाई, समाप्त होते रोजगार और बढ़ती बेराजगारी, औद्योगिक बीमारी में होती वृद्धि, रोजाना होते भ्रष्टाचार व घोटालों के खुलासे, जो कि नैगमिक समर्थक आत्मघाती नवउदारवादी नीतियों का परिणाम होते हैं। हमने यह भी रेखंकित किया था कि भाजपा जनता के गुस्से की इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर रही, जो कि स्वयं भी इन्ही घातक नीतियों की समर्थक है।

1.2.2 15वीं लोकसभा चुनावों के बाद सम्पन्न हुए सीटू के महाधिवेशन से लेकर हर एक जनरल कौंसिल एवं कार्य समिति की मीटिंगों में हम सरकार की राजनैतिक, आर्थिक एवं विदेश नीति में दक्षिणपन्थी झुकाव की चर्चा करते रहे हैं। हम दृढ़तापूर्वक कहते आ रहे हैं कि यह स्थिति बहुत हद तक, बढ़ते आर्थिक संकट में देश के सम्पूर्ण शासन पर नैगमिक कब्जे के हालात का रास्ता तैयार कर रही है। इसी के अनुसार हम ने सीटू के 14वें महाधिवेशन में यह तय किया था कि 'सरकार की राजनैतिक–आर्थिक नीतियों में दक्षिणपन्थी झुकाव का मुकाबला करने के लिए सरकार की नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध मेहनतकशों के संयुक्त संघर्षों को नयी उँचाईयों पर ले जाने तथा इसके लिए स्वतंत्र पहलकदमी अत्यंत जरुरी है।' सीटू के 14वें महाधिवेषन में सीटू यूनियनों का आव्हान् किया था कि वे न सिर्फ अपनी माँगों के लिए संघर्ष करें बल्कि शासक वर्गों की जन विरोध नीतियों एवं उसके हिमायतियों का भी पर्दाफाश करने के लिए लगातार अभियान चलाऐ।

1.2.3 सीटू के 14वें महाधिवेशन में, सम्पूर्ण संगठन को अपना अभियान हर मेहनतकश एवं हर क्षेत्र जक ले जाने के लिए हर एक स्तर पर पूरी तरह से तैयार करना है। प्रत्येक राज्य कमैटी और औद्योगिक महासंघ को इस अभियान एवं वामपंन्थ विकल्प के प्रचार की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी यूनियन स्तर की कमैटियों को राजनैतिक, सांगठनिक एवं समझदारी के स्तर पर तैयार करना ही होगा, "पहुँच से बाहर के मजदूरों तक पहुँचना" है। और यह संदेश पहुँचाना हमारे रोजमर्रा के काम का हिस्सा होना चाहिए – का आव्हान् किया था।

1.2.4 लोकसभा चुनावों के चुनावों के परिपेक्ष में अगस्त 2013 में जयपुर में सम्पन्न हुई सीटू की कार्य समिति की बैठक में भी यह दुहराया गया था।

1.2.5 लेकिन हम अपनी परिकल्पित अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को प्रभावी तौर तरीके से नहीं निभा सके। हम साम्प्रदायिक एवं जनता के अधिकारों व एकता पर कुप्रभाव डालने वाली, खतरनाक नैगमिक समर्थक नीतियों की समर्थक भाजपा का जनता के बीच पर्दाफाश नहीं कर सके। आर्थिक नीति के मामले में भाजपा और काँग्रेस दोनों ही एक जैसे हैं, यह हम जनता को नहीं समझा सके। एन.डी.ए. शासक के समय के अनुभव से यह भी स्पष्ट है कि उसी अर्थ नीति को सख्ती

से लागू करने के मामले में भाजपा कहीं अधिक आक्रामक है। मिसाल के तौर पर हम यह बताने में असफल रहे कि भाजपानीत एन.डी.ए. सरकार ने ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके उपभोक्ता वस्तुओं के लिए सट्टा बाजारियों के लिए रास्ता खोला था, भाजपानीत एन.डी.ए. सरकार ने ही ईंधन (खनिज तेल) मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करके आवश्यक वस्तुओं के बाजार में सट्टा बाजारियों को भारी मुनाफाखोरी करने का मौका उपलब्ध कराया। यह एक ऐसा गुनाह है जिसमें भाजपानीत एन.डी.ए. सरकार और काँग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार दौनों ही बराबर की हिस्सेदार रही हैं। सिर्फ वामपन्थी दल ही इसके सख्त विरोध में रहे हैं। तृणमूल काँग्रेस सहित अन्य सभी पार्टियाँ इस गुनाह के साथ रही हैं। हम यह संदेश जनता के बहुसंख्यक हिस्सों में ले जाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं।

1.2.6 हमारा काम था, नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना और नैगमिक समर्थक नवउदारवादी नीतियों का खुलासा करने के साथ ही साथ भाजपा का साम्प्रदायिक का पर्दाफाश करना और नवउदारवादी नीतियों की समर्थक सरकारों का साथ देने वाली अन्य सभी पूँजीवादी पार्टियों का भी खुलासा करना। हमारा काम भाजपा/आर.एस.एस. के द्वारा अपने घ्रणित राजनीतिक हित के लिए जनता और मेहनतकशों में फूट डालने के कुकृत्य का पर्दाफास करना ही हमारा काम था। भाजपा द्वारा काँग्रेस पर 'नीतिगत अकर्मण्यता' का आरोप लगाने का अर्थ जनविरोधी नीतियों का विरोध नहीं बल्कि इन नीतियों को अधिक आक्रामकता से लागू करने की मंशा जाहिर करना ही रहा है।

1.2.7 भाजपा द्वारा 'नीतिगत अकर्मण्यता' का आरोप काँग्रेस सरकार का, वित्तीय व बीमा क्षेत्र का पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र व ढ़ाँचागत क्षेत्र का पूरी तरह से निजीकरण करने और सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बेरोकटोक आने, में काँग्रेस सरकार के असफल रहने पर पैदा हुआ है। क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड़ यूनियनों के संयुक्त संघर्षों के दबाव में काँग्रेस सरकार द्वारा नवउदारवादी सुधारों के मामले में धीमा या आंशिक रुप से लागू करना ही, कथित 'नीतिगत अकर्मण्यता' है। लेकिन भाजपा ने ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन की इस उपलब्धि को बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करते हुए जनता के असंतोष को 'नीतिगत अकर्मण्यता' कहकर नवउदारवादी नीतियों को अधिक आक्रामक तरीके से लागू करने का जनादेश प्राप्त कर लिया है। नवउदारवादी नीतियों में विघ्न पैदा करने में सफल होने के बावजूद भी, वर्गीय मुद्दों पर केन्द्रित स्वतंत्र अभियान चलाकर, उसका राजनैतिक लाभ उठाने में हम पूरी तरह से असफल रहे हैं।

1.2.8 यह कमी या असफलता, मेहनतकश जनता के बीच अभियान चलाने के मामले में हमारी वर्गीय समझदारी एवं सांगठनिक कमजोरी का ही परिणाम है। इसने हमारे वर्गीय दुश्मनों को मिथ्या विकास और बेहतर सरकार के झूठे वायदों से परम्परागत रुप से वामपन्थी प्रभाव वाले मजदूरों को भी बरगलाने में सफलता मिली है। जनता की ज्वलन्त समस्याओं को गैर–राजनैतिक बनाने तथा नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध मार्चा लेने वाली प्रमुख ताकत मेहनतकशों को वर्गीय विचारधारा से दूर करने की, पूँजीपतिवर्गों की साजिश के विरुद्ध राजनैतिक लड़ाई लड़ने के लिए वर्गीय दृष्टिकोण एक आवश्यक तत्व है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नैगमिक वर्ग की देखरेख और नैगमिक नियंत्रित मीडिया के सीधे हस्तक्षेप से इस साजिश ने चौतरफा अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसके मुकाबले हम कुछ खास नहीं कर पाए। वर्गीय दृष्टिकोण की इस कमजोरी के परिणामस्वरुप हमारा प्रचार इस हद तक सतही था कि जहाँ वामपन्थी उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे वहाँ भी हम अपने सदस्यों और उनके परिवारों को भी समझा नहीं पाए। हम मेहनतकशों की जीविका से जुड़े सवालों पर बहुत से संघर्षों का नेतृत्व करते हैं और उनमें लाखों मजदूरों को शमिल करते हैं, परन्तु हम उनकी राजनैतिक चेतना को विकसित नहीं कर पाऐ हैं। हम साजिशों का मुकाबला वर्गीय समझदारी के साथ नहीं कर पाए, जिसके परिणामस्वरुप हमने अपने वर्ग के एक बड़े हिस्से के समर्थन को खोया है।

1.2.9 अपने वर्गीय काम को समझकर तय कर लेने और बार–बार दुहराते रहने के बावजूद भी इस गम्भीर कमजोरी के लिए सम्पूर्ण सीटू जिम्मेदार है। सीटू केन्द्र अपने राज्य स्तरीय नेतृत्व के साथ तालमेल, सामजस्य बनाकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के काम को लागू करने में असफल रहा है। यह कमजोरी और कमी, निचले स्तर अर्थात् यूनियन के स्तर तक

सीटू कार्यकताओं को वर्गीय दृष्टिकोण से तैयार करने तथा सभी मेहनतकशों के बीच जाकर उनकी राजनैतिक समझ तैयार करने में, अपने दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा करने में, कमी साफतौर पर नजर आती है।

1.2.10 यद्यपि सभी राज्यों में सीटू कार्यकर्ताओं ने वामपन्थी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने, भारी फण्ड एकत्र करने, लाखों की तादाद में चुनाव प्रचार सामग्री छापकर सीटू सम्बद्धित एवं मित्र यूनियनों और मजदूरों के बीच प्रचार करने की बहुत कोशिशें भी की हैं, परन्तु यह सब एक सीमा से आगे नहीं जा सका है। जैसा कि चुनाव परिणामों से स्पष्ट होता है कि यह सब आम मजदूरों और उनके परिवारों का विश्वास, वामपन्थी उम्मीदवार के पक्ष में जीतने के लिए काफी नहीं रहा है। यूनियन स्तर की कमेटियों द्वारा बहुसंख्यक मजदूरों और उनके परिवारों के बीच मजदूर वर्ग एवं वामपन्थ की विचारधारा के संदेश को ले जाने के महत्वपूर्ण काम पहलकदमी का भारी अभाव साफ दिखता है। सभी राज्यों के जनरल कौसिंल सदस्य और फेडरेशन के सदस्य इस पहलू पर चर्चा करके अपना अनुभव और अपनी राय स्पष्ट करें।

1.2.11 चूंकि अब स्थिति एक दम से भिन्न है इसलिए हमारे काम के इस पहलू पर अधिक जोर देना जरुरी हो गया है। अपनी योजनाओं के अनुसार समूचे चुनाव को, एक ओर धुर दक्षिणपन्थी भाजपा के पूरी तरह से पक्ष में तो दूसरी ओर वामपन्थ को किनारे लगाने के लिए पूँजीपति वर्गों ने अभूतपूर्व एवं बेहद आक्रामक तरीके से काम किया है। उनके लिए ऐसा करना बहुत ही जरुरी भी था क्योंकि नवउदारवादी साजिशों के द्वारा लोकतांत्रिक सस्थाओं और जनता को डराकर रखने की कोशिशों में सबसे बड़ी बाधा ही वामपन्थ है। उनकी यह आक्रामकता दिखाती है कि पूँजीवाद आकंठ डूबा हुआ है, और उस संकट से वह मजदूरों और आम जनता के कीमत पर ही उबरना चाहता है।

1.2.12 मजदूर आन्दोलन और वामपन्थ को दर किनार करने की कोशिशें आने वाले बहुत ही कठिन दिनों की ओर इशारा करती हैं। सिर्फ मजदूर आन्दोलन और वामपन्थ ही इन हमलों का विरोध करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि चुनावों में मिली भारी हार के बावजूद भी पूरे देश भर में, नैगमिक नियंत्रित मीडिया का वामपन्थ के खिलाफ कुप्रचार लगातार जारी है। इस पूरे कुप्रचार का केन्द्र बिन्दु नीतियों पर वामपन्थ के दृष्टिकोण को कमतर बताने और उसे अप्रासंगिक सिद्ध करना ही है। इसी कारण प० बंगाल में मात्र दो सांसदों में ही सीमति रह जाने के बावजूद भी वामपन्थी दलों और उनके समर्थकों सहित आम जनता पर आज भी हमला अधिकाधिक क्रूरता के साथ जारी है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी वामपन्थी कार्यकर्ताओं की हत्याओं की संख्या में हर दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। सीटू के अनेकों दफ्तरों पर हमले हुए है और उन्हें लूट लिया गया है, सीटू के अनेकों कार्यकर्ता जानलेवा हमलों में बुरी तरह से घायल हुए है और झूठे मुकदमों में भी फंसाया गया है। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही बहादुरी के साथ इन हमलों का सामना कर रहे हैं और अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

1.3 अनिष्टकारी लक्षण

1.3.1 चुनावों के बाद की स्थिति ने मजदूर आन्दोलन के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। नयी सरकार में भाजपा को अकेले ही लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल है जिसने अर्थ व्यवस्था को नियंत्रणमुक्त एवं निजीकरण करने तथा बड़े–बड़े निगमों एवं देशी–विदेशी बड़े व्यापारिक घरानों को भारी रियायतें जारी करने में पूरी आक्रामकता अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। भाजपा के चुनाव घोषणा–पत्र में इस बारे में कोई शब्द नहीं लिखा गया है। निवेश के अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के मामले में घोषणा–पत्र में 'कर का आतंक नहीं' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ यह बिलकुल भी नहीं है कि आम जनता को कर से कोई मुक्ति या छूट मिलेगी, बल्कि इसका उल्टा ही होगा। इसका अर्थ यह है कि करों में 3 लाख करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक की छूट पाने वाले तथा दिसम्बर 2013 तक 5.10 लाख करोड़ से अधिक कर का भुगतान न करने वाले बड़े निगमों और बड़े व्यापारिक घरानों को करों में भारी छूट वर्तमान भाजपा सरकार देने का इरादा रखती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी यह मंशा स्पष्ट हो गयी है। और यह सरकारी छूट

जो राष्ट्र के कोष से दी जानी हैं, और बजट घाटे को सीमित करने के लिए इसकी भरपाई, आम जनता पर करों का भारी बोझ डालकर, जनता को मिलने वाली राहतों तथा कल्याणकारी खर्चों में कटौती करके और जनोपयोगी सुविधा खर्च में कटौती करके ही की जाएगी।

1.3.2 राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का निजीकरण उनके एजेण्डे में प्राथमिकता पर है। यहाँ तक कि मंत्रिमण्डल के गठन से पहले ही रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गयी पी.जे. नायक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बैकिंग सैक्टर के निजीकरण का खाका तैयार कर लिया गया है और राष्ट्रीय मीडिया में उसका प्रचार भी बड़े पैमाने पर किया गया है। यह अब बीमा क्षेत्र के लिए भी किया जा रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, बिजली आदि सहित उर्जा क्षेत्र जो कि देश की जीवन रेखा है और अभी तक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में है, उसे निवेश को बढ़ाने के नाम पर बेचने की तैयारी है। यह सभी नवउदारवादी कदम जो कि भाजपा के चुनाव घोषणा–पत्र का अहम् हिस्सा है, और इस पर कार्यवाही की पूरी तैयारी है, ताकि देश समूची अर्थव्यवस्था को देशी–विदेशी धन्नासेठों के हवाले किया जा सके। यह हमारे राष्ट्र की आत्म निर्भरता और विकास के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। यह मेहनतकशों के अधिकारों और जीविका को भी खतरे में डाल देगा। केन्द्र की मदद से संचालित आँगनबाड़ी, मिड–डे–मील तथा शिक्षा एवं चिकित्सा से जुड़ी तथा अन्य जनोपयोगी योजनाओं को समाप्त या निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी है, इसके लिए यू.पी.ए. सरकार ने पहले ही शुरुआत कर दी थी।

1.3.3 और अंत में मजदूरों के बारे में भाजपा के चुनाव घोषणा–पत्र में स्पष्ट किया है कि वह लचकदार श्रम सम्बन्धों के हिमायती हैं और वह श्रम कानूनों में उलट–पलट अवश्य करेगें जिसका मतलब हैं कि श्रम कानूनों में मजदूरों का दबाकर रखने वाले तथा मालिकान के पक्ष में बदलाव किए जाऐगें। भाजपा शासित राजस्थान में सरकार ने घोषणा कर दी है कि मालिकान के हाथ मजबूत करके मजदूरों को नौकरी पर रखने या निकालने के मामले में बन्धनमुक्त करने जा रहे हैं और यूनियन का गठन करना, पंजीकरण और मान्यता प्राप्त करने आदि के अधिकारों पर तमाम तरह की पाबन्दियाँ थोप दी गयी हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन का केन्द्र बिन्दु हैं कि वर्तमान 100 के स्थान 300 मजदूरों तक के कारखाना मालिक को छंटनी का स्वतंत्र अधिकार दिया जाए। अधिकांश कारखानों को श्रम कानूनों के पालन से मुक्त करने के इरादे से वर्तमान सीमा 20 से बढ़ाकर 50 करने के लिए कारखाना कानून में संशोधन करने का इरादा है। मुख्य नियोक्ता को ठेका मजदूरों की किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए ठेका मजदूरी कानून में संशोधन करने का इरादा है। फिक्की जैसे बड़े व्यापारिक संगठनों ने नवउदारवादी सुधारों के बारे में अपना जो माँग–पत्र प्रस्तुत किया है, और जो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा भी है, उसके सभी बिन्दु ही नहीं कहीं–कहीं तो उसी भाषा में भाजपा के चुनाव घोषणा–पत्र में भी जिक्र किया गया है।

1.3.4 नरेन्द्र मोदी सरकार ने शासन को जो तरीका अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए भारी खतरा पैदा करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर राष्ट्रपति प्रणाली थोपी जा रही है। यह अधिनायकवाद का अशुभ संकेत ही है।

1.3.5 साम्प्रदायिक एवं विघटनकारी मुद्दे भाजपा की विचारधारा और उनकी कारगुजारियाँ एक अहम् हिस्सा होता है। सामाजिक असंतोष को फासीवादी तरीके से विघटनकारी रुप देने में उन्हे कोई झिझक नहीं होती है। उनका अतीत ऐसी ही कारगुजारियों का रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव प्रचार के दौरान प० बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश आदि में भाजपा, आर.एस.एस. और उससे जुड़े संगठनों विघटनकारी, नस्लवादी और बांग्लादेश से घुसपैठ जैसे मुद्दों को खूब उछाला है, ताकि वोटों का धुव्रीकरण किया जा सके। यह एक दम से स्वाभाविक ही होगा कि भाजपा सरकार साम्प्रदायिक आधार पर धुव्रीकरण के मकसद से इसके लिए सत्ता का दुरुपयोग भी करे। अभी हाल की पूना की साम्प्रदायिक हिंसा और स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय से संविधान की धारा 370 का हटाने का मुद्दा उठाना इस ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियाँ है।

2. आर्थिक स्थिति

2.1 अर्थ व्यवस्था इस समय बहुत ही बुरी हालत में है। महँगाई और बेराजगारी बेहताशा बढ़ती ही जा रही है। सकल घरेलू उत्पादन में 2010–11 से लगातार गिरावट दर्ज हो रही है।

2.2 पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक उत्पादन के बावजूद भी खेती बहुत अधिक गम्भीर दबाव में हैं। कृषि पर निर्भर जनता, चाहे वह मध्यम किसान हो या छोटा अथवा सीमान्त किसान या खेतिहर मजदूर सभी आमदनी घटने बेहद तंगी झेल रहे हैं। यह स्थिति लोगों को खेती–किसानी छोड़कर बेरोजगारों या अल्प रोजगार वालों की फौज में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है।

2.3 औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट है। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष की आखिरी तिमाही में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज हुई और यह स्थिति लगातार बनी हुई थी। इस स्थिति में अनेकों उद्योग बन्दी या उत्पादन कार्य की बन्दी की हालत हो गयी है। इस बन्दी और शट–डाउन के सारे बोझ को मजदूरों पर डाल दिया गया जबकि मालिकान पूरे मजे में हैं।

2.4 उदाहरण के तौर पर पिछले एक वर्ष के दौरान प० बंगाल में ही बिरला की हिन्दुस्तान मोटर्स, रुईया की जेसॉप और डनलप व डकबैक आदि औद्योगिक इकाईयाँ, हजारों मजदूरों को भारी परेशानी में डालते हुए बन्द कर दी गयी है। ये बड़े नैगमिक घराने बहुत भारी मुनाफे कमा रहे हैं परन्तु बाजार में उत्पादों की स्थिति के बहाने से इन इकाईयों को बीमार घोषित करके सारा बोझ स्थायी एवं ठेका मजदूरों पर डाल दिया गया है। प० बंगाल में जूट मिलों के उत्पादन में भारी कटौती की जा रही है, और यह सब केन्द्र सरकार की बहुराष्ट्रीय निगम समर्थक नीति के तहत और राज्य सरकार की मिली भगत से किया जा रहा है, जिसका सारा बोझ पूरी तरह से मजदूरों पर डाल दिया गया है। इस सब के जरिए जूट उद्योग ने जो संसाधन पैदा किए थे उनका प्रयोग कहीं अन्यत्र लाभकारी उद्योगों में लगाकर, भारी मुनाफे कमाने के लिए निजी मिल मालिकों द्वारा किया जा रहा है। अनेक उत्पादक इकाईयों को रीयल स्टेट व्यापार में अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए करने की कोशिशें भी हुई हैं। नवउदारवादी निजाम में उत्पादक इकाईयों को रीयल स्टेट में बदलना, औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध और उत्पादक रोजगार को एक प्रकार से विकृत करने का प्रयास ही कहा जाएगा। तमिलनाड़ में 8000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाली नोकिया की उत्पादक इकाई बन्द होने के करार पर है, जबकि माक्रोसॉट ने पूरी नोकिया कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया है। नोकिया के इस संकट के कारण, आस–पास स्थिति उसकी सहायक एवं आपूर्ति करने वाली अनेक इकाईयाँ बन्द होनी शुरु हो गयी है नतीजन बड़े पैमाने पर नौजवान मजदूर बेरोजगार होने जा रहे हैं। इसी प्रकार का अनुभव अन्य राज्यों में भी है। उपस्थित कॉमोड्स् से अनुरोध है कि अपने पास उपलब्ध जानकारियाँ साझा करके इस रिपोर्ट को मुकम्मिल करने में सहयोग करें।

2.5 चुनावों के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश में लगातार वृद्धि का मीडिया और नवउदारवादियों ने भरपूर गुणगान भी किया है। यद्यपि इसके माध्यम से चालू खाते के घाटे में कुछ कमी अवश्य आयी है, परन्तु विदेशी संस्थागत निवेश न तो स्थायी है और ना ही इससे रोजगार पैदा होता है।

2.6 इस सम्बन्ध में एक मुद्दे को समझना जरुरी है। अक्सर कारखाना बन्दी और बीमारी, बाजार में गिरावट, प्रतियोगिता में कमी और तकनीक में पिछड़ापन लाती है जिसके कारण उसका सारा बोझ मजदूरों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन निजी क्षेत्र में उद्योगों में बन्दी या शट–डाउन आदि वास्तव में मजदूरों की जीविका की परवाह किए बिना ही सिर्फ पूँजी को अधिक लाभकारी उद्यमों या कारगुजारियों की ओर ले जाने औजार के रुप में इस्तेमाल होते हैं। पूँजीवाद इसी प्रकार काम करता है, नवउदारवादी निजाम में इस प्रकार सभी हथकण्डे ही इसके संकट के मूल कारण हैं। मजदूर अकेले

ही इसकी सजा झेलता है, जबकि इस बन्दी, औद्योगिक बन्दी या बीमारी के बावजूद भी मालिकान अधिकाधिक धनी होते जाते हैं।

2.7 अर्थव्यवस्था में इस कदर निराशा के बावजूद भी नयी सरकार ने अपने पहले बजट से पहले ही अपना असली रंग दिखाना शुरु कर दिया है। सरकार ने रोजाना यात्रा करने वाले कामकाजी लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मासिक टिकट सहित रेल किराऐ में 14.25 प्रतिशत की वृद्धि, माल भाड़े में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि और उस पर 3 प्रतिशत का सरचार्ज आदि सिर्फ कैबीनेट में निर्णय लेकर एक आदेश के जरिए कर दिया है, जिससे सरकार की आम जनता के प्रति आक्रामक क्रूरता स्पष्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा बार–बार घोषित 'कठोर फैसले' के द्वारा रसोई गैस, प्राकृतिक गैस, और अन्य जनोपयोग की वस्तुओं दामों में वृद्धि करने की मंशा साफ हो चुकी है। हमारी जनरल कौंसिल मीटिंग के दिन ही बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार के जन विरोधी एवं मजदूर विरोधी कदमों के खिलाफ सीटू को प्रभावशील प्रतिरोध खड़ा करना ही होगा।

3. पिछले दौर के संघर्षों के बारे में

3.1 हमारी कार्यसमिति की अगस्त 2013 में सम्पन्न मीटिंग के बाद, सभी राज्यों व सैक्टरों में महीनों चले सघन अभियान के बाद प्रमुख रुप से 21 दिसम्बर 2013 को हुआ ट्रेड़ यूनियनों संयुक्त कार्यक्रम "संसद चलो" रहा है। सभी केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों के संयुक्त आव्हान पर इस कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग 2.5 लाख मजदूरों ने शिरकत की। इसमें सर्वाधिक मजदूर सीटू और एटक एवं उनसे जुड़े फैडरेशनों की ओर से शामिल हुए। अन्य संगठनों की ओर से सांकेतिक प्रतिनिधित्व ही था। राज्यों तथा विभिन्न फैडरेशनों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सीटू के 72,796 मजदूर इस संसद चलो में शामिल हुए। मजदूरों की भागीदारी दक्षिणी एवं सुदूर पूर्वी राज्यों से अच्छी संख्या के साथ मजदूर सभी राज्यों से शामिल हुए। प्रमुख भागीदारी महाराष्ट्र सहित आस–पास के हिन्दीभाषी राज्यों से ही थी। इसके अलावा फैडरेशन ऑफ सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट इम्पलाईज, स्टेट गवर्नमैन्ट इम्पलाईज, बी.ई.एफ.आई., ए.आई.आई.ई.ए. और बी.एस.एन.एल.ई.यू. सहित हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले स्वतंत्र फैडरेशनों की ओर से लगभग 15,865 इम्पलाईज ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यवार शिरकत का व्यौरा अलग से प्रसारित किया जा चुका है।

3.2 जिन राज्यों से मजदूर दिल्ली नहीं पहुँच सकते थे, उनका केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों के मंच से, उसी दिन राज्य एवं जिला स्तर पर भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने का आव्हान् किया गया था। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, केरल, प० बंगाल और त्रिपुरा में बड़े आयोजन हुए। केरल में इन्टक के साथ मिलकर कोलम, इडुक्की और कन्नूर को छोड़कर शेष सभी जिलों में 14 केन्द्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में 1,11,800 मजदूरों ने शिरकत की। प० बंगाल में 13 जिलों में आयोजित प्रदर्शनों में कुल 59,900 मजदूरों ने शिरकत की। त्रिपुरा में 74 केन्द्रों पर 34,585 मजदूरों ने असम में 27 में से 21 जिलों में 9,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। तमिलनाड़ के जिलों में रैलियाँ आयोजित की गयी परन्तु विस्तारित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। झारखण्ड के जमशेदपुर में एक संयुक्त प्रदर्शन आयाजित किया गया। किसी अन्य राज्य से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

3.3 सीटू की कार्यसमिति की मीटिंग के बाद के दौर में कई महत्वपूर्ण संघर्ष हुए हैं जिनमें सीटू की पहल उल्लेखनीय रही है। यह उल्लेखनीय है कि रेल किराए और भाड़े में भारी बढ़ोत्तरी के खिलाफ सीटू ने अधिकांश राज्यों में रेल/रोड़ जाम करने सहित प्रदर्शन आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों तथा उनमें मजदूरों की भागीदारी के बारे में राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त होनी है। साथियों से अनुरोध है कि इस बारे में लिखित रिपोर्ट इसी मीटिंग में दें।

3.4 कर्नाटक स्थित जापानी बहुराष्ट्रीय कम्पनी टोयोटा के मजदूरों ने मार्च–अप्रैल 2014 के दौरान हड़ताल की। कम्पनी ने तालाबन्दी घोषित कर दी, बाद में तालाबन्दी वापस लेकर मारुति की तरह ही अच्छे आचरण के पत्र पर हस्ताक्षर करने

की शर्त पर काम पर लौटने के लिए कहा। मजदूरों ने अस्वीकार करते हुए बहादुरी से हड़ताल जारी रखी। इस हड़ताल नेतृत्व स्वतंत्र यूनियन ने किया और सीटू ने एकजुटता की कारवाही के साथ ही साथ राज्य के श्रम विभाग में मुद्दे को उठाया। राज्य के श्रम विभाग ने हस्तक्षेप करके कम्पनी को अपने कदम अर्थात् काम पर आने की शर्त वापस लेने के लिए मजबूर किया।

3.5 अन्य संघर्षों में हिमाचल में 5 मिनी हाईडेल परियोजनाओं के मजदूरों की 11 दिन की हड़ताल, चम्बा जिले में स्थित चन्जू हाईडेल परियोजना में 10 दिन की हड़ताल और अक्टूबर–नवम्बर 2013 में सीमेन्ट मजदरों की हड़ताल हैं। जनवरी 2014 में हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों की 4 दिन की हड़ताल, अनुचित सेवा शर्तें थोपने के खिलाफ 1–2 अप्रैल 2014 को मुम्बई ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल जिसने मुम्बई शहर को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस एकतरफा निर्णय को महाराष्ट्र सरकार को वापस लेना पड़ा। आन्ध्र प्रदेश के बँटवारे से उत्पन्न भारी तनाव और अफरा–तफरी के दौरान भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी माँगों को लेकर एक सफल और जबरदस्त प्रदर्शन का आयोजन किया।

3.6 केन्द्र सरकार के 13 लाख कर्मचारियों ने फरवरी 2014 में 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल की और 10 लाख बैंक कर्मचारियों ने 10–11 फरवरी 2014 को देशव्यापी हड़ताल की।

3.7 पिछले दौर में सभी स्कीम वर्कर्स, आँगनबाड़ी, मिड–डे–मील और विशेष रुप से आशा वर्कर्स ने अपनी माँगों को लेकर हड़ताल सहित आन्दोलन पर रह हैं। महाराष्ट्र में आँगनबाड़ी वर्कर्स और कर्नाटक में मिड–डे–मील अपनी कुछ माँगें हासिल करने में सफल भी रहे हैं। अविभाजित आन्ध्र प्रदेश में आँगनबाड़ी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, भारी संख्या में सड़क पर उतरे, विपरीत राजनैतिक हालात में भी अपने वेतन–भत्ते में बढ़ोत्तरी हासिल करने में सफल रहे। प० बंगाल में हमारी आँगनबाड़ी यूनियन ने आँगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स की जबरन सेवानिवृति के खिलाफ अनेकों बार जिला स्तर पर तथा कोलकाता में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

3.8 पिछले दिनों में तकरीबन सभी राज्य कमैटियाँ, फैडरेशन और यूनियनें, राज्य एवं जिला स्तर पर आन्दोलनों में व्यस्त रही हैं। केरल राज्य कमैटी ने मजदूरों की माँगों को लेकर और सरकार की नीतियों के खिलाफ सभी श्रेणी और सभी प्रकार के मजदूरों को लेकर बहुत बड़ी रैलियाँ करके राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के समक्ष शानदार प्रदर्शन किए हैं। इस के बारे में विस्तारित जानकारी अलग कार्यवाही रिपोर्ट में दी जा रही है।

3.9 हिन्द मोटर्स, जेसोप, डकबैक आदि बड़ी औद्योगिक इकाईयों की बन्दी और उत्पादन में कटौती तथा जूट मिलों में इस बन्दी / शट–डाउन के नए चलन के खिलाफ प० बंगाल में सीटू की पहल पर 3 जून 2014 को एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया और 11 जून 2014 को कोलकाता में एक विशाल जुलूस निकाला गया और बन्दी और कटौती की इस प्रवृत्ति के खिलाफ प्रभावित जिलों में सीटू की स्वतंत्र पहल पर अनेक प्रकार की विरोध की कारवाहियाँ हो रही हैं।

3.10 तमिलनाडु राज्य कमैटी की यह पहल उल्लेखनीय है कि उसने मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के समर्थन में एकजुट अभियान चलाकर, हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन की मदद के लिए 5 लाख रुपए एकत्र किए गए हैं।

3.11 घ्यान रहे कि प० ब्रगाल में अक्टूबर 2013 से ही हमारे कॉमरेडस् तृणमूल काँग्रेस के गुण्डों और अन्य आसामाजिक तत्वों द्वारा भारी हमलों का सामना कर रहे हैं। ये हमले चुनावों के दौरान भी चलते रहे और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी जारी हैं। बहुत से साथी और समर्थक इन हमलों में अपनी जान गवां चुके हैं और हजारों की तादाद में अपने घर और काम के स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारे सैकड़ों कॉमरेड़ और कार्यकताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया

गया है, जिनमें से अनकों पर गैर–जमानती मामले बनाऐ गये हैं जिसके कारण वे महीनों जेल में बन्द हैं। इन कारगुजारियों को पुलिस बड़ बेशर्मी से संरक्षण दे रही है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद इन हमलों में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है और इसमें शहर और देहात में मेहनतकशों को शिकार बनाया जा रहा है। हजारों छोटे किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करके, अनेकों कारखानों से मजदूरों को निकालकर ठेकेदारों की सुविधा के अनुसार उनके स्थान पर कम वेतन पर नए मजदूरों का रखा जा रहा है, आतंक और हिंसा के द्वारा अनेकों सहकारी समितियों और स्वावलम्बी समूहों का काम करने का रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, और छोटी दुकानों एवं छोटे व्यापार को हिंसा और अवैध वसूली के द्वारा जबरन बन्द कराया जा रहा है, यह सब करके जनता की जीविका पर हमले किए जा रहे हैं। यह सब प्रशासन की मदद से तृणमूल काँग्रेस के गुण्डों की लूट और जबरन वसूली की व्यवस्था के विरोध को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य मकसद वामपन्थ को कमजोर करके समाप्त करना है, क्योंकि सिर्फ वामपन्थ ही बहुराष्ट्रीय एवं बड़े–बड़े देशी व्यापारिक घरानों की, तृणमूल काँग्रेस के द्वारा प० बंगाल में तथा केन्द्र में भाजपा के माध्यम से लूट का सशक्त विरोध कर सकता है। इसलिए जनवादी आन्दोलन और प० बंगाल में वामपन्थ पर इस फासीवादी हमलों के खिलाफ देशव्यापी और विस्तारित अभियान छेड़ने की सख्त आवश्यकता है। सीटू को यह जिम्मेदारी अपेक्षित गम्भीरता के साथ एकजुटता की कार्रवाहियाँ संगठित करने की जरुरत है।

4. निर्धारित सांगठनिक जिम्मेदारियों का पुनर्वालोकन

4.1 हमें सीटू और मजदूर आन्दोलन द्वारा निभायी गयी भूमिका और प्रतिरोध, संघर्षों एवं अभियानों की तैयारियों में तथा सांगठनिक तैयारियों में वर्गीय दृष्टिकोण की कमजोरी से निष्कर्ष निकालना होगा। हमारी सांगठनिक तैयारी और आन्दोलन व संघर्ष विकसित करने की पहलका सीधा सम्बन्ध, स्थितियों के बारे में हमारी समझदारी से है, जिससे हम अपनी इस समझदारी को संगठन के जमीनी स्तर तक ले जाने में हमारी कोशिशों का तय करता है।

4.2 सीटू के 14वें महाधिवेशन ने अपने मुख्य राजनैतिक–सांगठनिक पर केन्द्रित रखते हुए नियत किया किः

- समूचे मजदूर वर्ग को एकताबद्ध करने के लिए, ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन में हासिल एकता को जमीनी स्तर पर लेकर जाओ।
- वर्ग संघर्ष को लगातार घनीभूत करो।
- अपनी माँगों की लड़ाई को समकालिकता और पूरे सचेतन प्रयासों के साथ, शासन की नीति से जोड़कर, घातक नीतियों का पर्दाफास करते हुए, इन नीतियों के समर्थकों का भी खुलासा करना।
- यूनियन / इकाई स्तर पर नेतृत्व को इस प्रकार तैयार करना कि जो मजदूर आन्दोलन की मुख्य धारा और जो हमारी पहुँच से बाहर हैं, उन तक पहुँचा जाए, इस अहम् जिम्मेदारी को पूरा करने में हमारी पूरी सदस्यता अर्थात् आम मजदूरों को भी शामिल किया जाए।

4.3 इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सीटू महाधिवेशन ने कुछ सांगठनिक एवं आन्दोलनात्मक पहलकदमियों को चिन्हित करते हुए गम्भीर निर्णय लिए थे, मिसाल के तौर पर;

1. संगठित क्षेत्र के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ही हमारे संगठन का विस्तार और सक्षम नेतृत्व का विकास, क्योंकि इसमें हम पिछड़ रहे हैं। नवउदारवादी निजाम में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बढ़ते ठेकेदारी करण एवं अस्थायीकरण के साथ

ही साथ कई अन्य कारणों से मजदूरों में रोष लगातार बढ़ रहा है। हमारे वर्गीय दुश्मनों और मीडिया के द्वारा मिथ्या आँकड़ों के द्वारा इस प्रकार का दुष्प्रचार चलाया जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में मजदूर आन्दोलन सिर्फ 8 प्रतिशत श्रम शक्ति तक ही सीमित है। कभी–कभी हमारे भी कुछ साथी इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था की जीवनदायिनी आधुनिक संगठित क्षेत्र में मजदूर आन्दोलन की दखलन्दाजी और चोट करने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। जब तक इस संवेदनशील और रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में मजदूर आन्दोन की प्रभावी मौजूदगी और इस क्षेत्र के मजदूरों को मजदूर वर्ग के नेतृत्व की पहली कतारों में नहीं लाते तब तक हम अपने लक्ष्य, शोषण की व्यवस्था की समाप्ति की ओर एक इंच भी आगे नहीं जा सकते। तो दूसरी ओर संगठित क्षेत्र के इतने बड़े सैक्टर के इतनी बड़ी संख्या के आधुनिक मजदूरों के बीच हमारी सांगठनिक मौजूदगी न होने का अर्थ यह है कि यह मजदूर हमारे दुश्मन वर्ग के मकड़जाल में फंसता चला जाएगा। यह मजदूर आन्दोलन की दखल करने और मारक क्षमता में भारी गिरावट ला रहा है।

इसके अतिरिक्त यह समझना ही होगा कि नवउदारवादी निजाम में संगठित क्षेत्र के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के ही मजदूरों की बनावट और उसके बुनियादी स्वरुप में भारी बदलाव आया है। इन नीतियों के तहत, अनेक प्रकार के बहानों से ठेका मजदूर कैजुअल मजदूर आदि के माध्यम से मजदूरों में विभिन्न प्रकार का विभाजन, भेदभाव पैदा कर दिया गया है। हमारा प्रमुख कार्य उद्योग के अन्दर से ही पहल करके ठेका मजदूरों को यूनियनों में संगठित करना और उनके आन्दोलनों को उद्योग के आन्दोलन से जोड़ना है। देश के मजदूर आन्दोलन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस सैक्टर की इन समस्याओं के समाधान के लिए मजदूर आन्दोलन को काम करने की आवश्यकता है।

पिछले दिनों में हमारा इस दिशा में कोई प्रयास नजर नहीं आता है। सीटू ने अपेक्षाकृत कमजोर हिन्दी भाषी राज्यों में कुछ पहल अवश्य की परन्तु हम अपने नेतृत्वकारी साथियों को ही क्रियाशील नहीं कर सके। यहाँ तक कि हमारे मजबूत क्षेत्रों में भी, संगठित निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में हमारी जो स्थिति सीटू के 14वें महाधिवेशन के समय थी उससे थोड़ा सा भी आगे गए हों नजर नहीं आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम हमारे संगठन में उपर से लेकर नीचे तक, समझदारी और निष्कर्ष को समावेश ही नहीं कर पाए हैं। हमारी समझादारी और गतिविधियों को, औपचारिकता और परम्परावादी रस्मआदायगी की जड़ता से मुक्त कराने के लिए इस मुद्दे पर जनरल कौंसिल मीटिंग में गम्भीरता से चर्चा करें। पूरी गम्भीरता और लगन के साथ सभी स्तरों पर अनवरत प्रयास करके अपनी इस अपाहिजगी से बाहर आना ही होगा।

2. हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में, जहाँ हमारी कुल सदस्यता का 70 प्रतिशत है, हमें अपने काम करने के सांगठनिक तौर तरीकों में गुणात्मक बदलाव की सख्त आवश्यकता है। हमने इस सैक्टर में संगठित और लगातार नवीनीकरण और असंगठित क्षेत्र से ही नेतृत्व के विकास करने के चेतनशील प्रयास के काम पर केन्द्रित किया था। नवीनीकरण की यह चेतनाशील पहल ही, हमारी सांगठनिक ताकत को मजबूत बना सकती है, वैसे भी इस सैक्टर में अत्यन्त अस्थिर एवं अनिश्चिता के चलते स्थायी और समझदारी से परिपूर्ण नेतृत्व का विकास असंगठित क्षेत्र के अन्दर ही करना जरुरी है, ताकि सीटू के संगठनकर्ता इतने विस्तृत असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों तक जा सकें, जो अभी संगठित नहीं किए ज़ा सके हैं।

हमने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमें व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित मुद्दों पर आन्दोलन विकसित करना है और संगठन तथा नेतृत्व को को भी इस दिशा में तैयार करना होगा। हम ने इस काम पर भी जोर दिया था कि हमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के असंगठित मजदूरों को अधिकाधिक सदस्य बनाना ही होगा, रोजमर्रा के काम के तौर पर इस प्रकार की पहल के लिए अपनी सदस्यता से भी आगे जाना होगा ताकि जिन तक नहीं पहुँचा जा सके हैं, उन तक पहुँचा जा सके और असंगठित क्षेत्र में नेतृत्व और पूरा वक्ती कार्यकर्ताओं को उनमें से ही विकसित किया जा सके। हम ने विशेष रुप से इस दिशा में बहुत ही थोड़ा सा ही किया है। हमें यह काम पूरी गम्भीरता के साथ आगे ले जाना होगा।

3. हम ने सामाजिक मुद्दों और पहचान की राजनीति से उत्पन्न समस्याओं पर अपने वर्गीय मंच से पहल और दखल करने के काम पर केन्द्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर देकर कहा था। इस सम्बन्ध में सीटू केन्द्र ने प्रयोग के तौर पर कुछ कमजोर राज्यों को शामिल करते हुए कुछ पहल की है। इस पहल में एक फैड़रेशन को भी शामिल किया गया। सम्बन्धित राज्य कमेटियों से सलाह मशविरा करके, रांची में जनजाति मजदूरों के मुद्दों पर एक मीटिंग बुलाने की योजना बनायी गयी जिसमें आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ से उन यूनियनों से प्रतिनिधियों को शामिल करना था जिनमें जनजाति मजदूरों की सदस्यता अच्छी खासी है। परन्तु सम्बन्धित राज्य कमेटियों ने या तो उचित प्रतिनिधित्व के बारे में या इस सम्बन्ध में जानकारियाँ एवं रिपोर्ट मुहैया कराने में सहयोग नहीं किया। इस अपेक्षित सहयोग की कमी के चलते सीटू केन्द्र एक और मीटिंग बुलाने में असहाय महसूस किया। यद्यपि उत्तरपूर्व में सम्पन्न हुई प्लान्टेशन सैक्टर में जनजाति मजदूरों की मीटिंग में बहुत ही अच्छे अनुभव एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हुई, उस क्रम में आगे की पहले के लिए ऑल इण्डिया प्लान्टेशन वर्कर्स फैडरेशन ने अपेक्षित विस्तृत लिखित रिपोर्ट मुहैया नहीं करायी। यह पहल असरदार नहीं हो सकी।

4. यद्यपि कामगार महिलाओं को संगठित करने तथा उनके बीच सक्रिय कार्यकर्ता एवं नेतृत्व विकसित करने की पहल करने का फैसला बहुत पुराना है, फिर भी इस सम्बन्ध अभी भी काफी कमजोरियाँ मौजूद हैं। सीटू केन्द्र ने इन कमियों को दूर करने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की थी। फिर भी अनेकों राज्यों ने इस वर्कशॉप और उसके निष्कर्षों को अपेक्षित गम्भीरता से नहीं लिया। जैसा कि 14वें महाधिवेशन में तय किया था, सामाजिक मुद्दों पर पहले करने के लिए अधिक ध्यान देना ही होगा।

5. हमने सरकार द्वारा निजीकरण के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों और जन सेवाओं से हाथ झाड़ लेने के प्रयासों के खिलाफ बहुत बड़े आन्दोलन खड़े किए है। 'आई.सी.डी.एस. बचाओ' अभियान में ए.आई.के.एस., ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. और ए.आई.डी. उब्ल्यू.ए. को शामिल करने की पहल की थी, जिसके महत्व को जयपुर में आयोजित कार्यसमिति की मीटिंग में विस्तार से रखा था। फिर भी बहुत ही कम राज्य कमैटियों ने इस काम को गम्भीरता से लिया है। कुछ एक राज्य सम्मेलन औपचारिकता भर के लिए ही किए गए। इस आन्दोलन में अन्य जन संगठनों को शामिल करके आई.सी.डी.एस. के निजीकरण के खिलाफ आन्दोलन को विस्तारित करने के लिए टिकाऊ प्रयास नहीं किए गए। इस कार्यक्रम के राजनैतिक महत्व को समझने में अपनी अधिकांश राज्य कमेटियाँ असफल हैं।

4.4 बुनियादी समस्या अपनी कमजोरियों से निकलने के अपने ही निर्णय को आत्मसात् करने को लेकर है। इसे समझना होगा ताकि सिर्फ औपचारिकता और रस्मअदायगी की बाधाओं से बाहर निकलकर, इसे संगठन के हर स्तर पर वास्तविक अर्थों ले जाया जा सके। इसके बिना आम मजदूर को हमारी राजनैतिक सांगठनिक लडाई में न तो शारीरिक रुप से ना ही मानसिक रुप शामिल किया जा सकता है। हमें सीटू के 14वें सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अपना आन्दोलनात्मक एवं सांगइनिक काम को पूरी गम्भीरता से अन्जाम देना चाहिए जो कि अब बदली हुई राजनैतिक परिस्थिति में कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है।

5. भावी कार्य

5.1.1 हमें ट्रेड़ यूनियनों के संयुक्त मंच को अधिकाधिक विस्तारित एवं मजबूत बनाने की पहल को जारी रखना ही चाहिए। हमें मजदूर आन्दोलन को एकताबद्ध रखते हुए मेहनतकश जनता को क्षेत्रीय एवं जमीनी स्तर पर एकता के सूत्र में पिरोने के काम को लगातार करते रहना होगा। धुर दक्षिणपंन्थी, साम्प्रदायिक ताकतों के सत्ता पर काबिज होने पर उत्पन्न चुनौतियों का सामना सिर्फ मजदूर वर्ग ही कर सकता है। इस दक्षिणपन्थी सत्ता के द्वारा मेहनतकशों पर किए गए हमले ही, सभी सम्बद्धताओं के शोषितों की एकता के कारण बनेगें। लेकिन यह अपने आप और स्वतःस्फूर्त तरीके से होने वाला नहीं है।

इसके लिए हमें लगातार चैतन्य होकर पहले करते हुए बनी हुई एकता को और अधिक विंस्तारित और मजबूत करते रहना होता और इसका विस्तार विभिन्न सेक्टरों में तथा इस एकता को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा।

5.1.2 सत्ता में परिवर्तन के बाद सभी ट्रेड़ यूनिंयन महासंघों ने नए वित्त मंत्री के साथ 6 जून 2014 को सम्पन्न हुई बजट पूर्व मीटिंग में अपना संयुक्त माँग–पत्र प्रस्तुत किया है। सभी ट्रेड़ यूनियनों ने जोर देकर नियंत्रण मुक्त करने और निजीकरण की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की और महँगाई पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने, श्रम कानूनों को पालन कराने और श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में समुचित धन आवंटित करने की माँग की। राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके ''हायर एण्ड फायर'' लागू करने तथा ट्रेड़ यूनियन के पंजीकरण में अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के कदमों पर बी.एम.एस. सहित सभी केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों ने जोरदार आवाज में विरोध किया। ऐसा विरोध संसद के अन्दर भी किया गया है।

5.1.3 केन्द्रीय श्रम मंत्री के साथ 24 जून 2014 को केन्द्रीय श्रम संघों की मीटिंग में एक आवाज में माँग की गयी कि नीतियों की दिशा में ऐसे बदलाव किया जाए ताकि मजदूरों के जायज अधिकारों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित की रक्षा की जा सकै। एकजुटता के साथ कहा गया कि राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का सदुपयोग बहुसंख्यक जनता के हित में किया जाए। ट्रेड़ यूनियनों सभी क्षेत्रों को सीधे विदेशी निवेश के लिए खोलने की नीति की सक्स्त विरोध दर्ज कराया, और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों एवं वित्तीय क्षेत्र सहित प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रण मुक्त करने, तथा सार्वजनिक क्षेत्र का आक्रामक विनिवेश करने व जनोपायोगी सेवाओं के निजीकरण पर सख्त एतराज किया। अपने 10 सूत्रीय माँग पर को दुहराते हुए सरकार से तुरन्त कार्यवाही करके माँगों को हल करने की की और श्रम कानूनों में माजिकों के हित में संशोधन करने पर सख्त एतराज दर्ज कराया।

5.1.4 ऐसरी संयुक्त पहलकदमी राज्य स्ता पर भी बढ़ रही है। प० बंगाल में उद्योगों की बन्दी के खिलाफ सभी केन्द्रीय श्रम संघों का संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया। इसके बाद 11 जून 2014 को कोलकाता में संयुक्त जुलूस निकाला गया। केरल तें मजदूरों के ज्वलंन्त सवालों पर सभी श्रम संघों का संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया। पोर्ट वर्कर्स फैड़रेशन ने 'मरक्ष्य बन्दगाहों को बचाओ' अपने अभियान के तहत एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय संयुक्त रुप् से किया है। अन्य राज्यों में भी राज्य कमेटियाँ और बड़े फैड़रेशन ऐसी ही पहल कर रहे हैं।

5.1.5 ऐसी खबरें हैं कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार मजदूरों पर बहुत घातक हमले करने जा रही है। वित्त, ढ़ाँचागत, प्रतिरक्षा, उर्जा, कोयला और प्राकृतिक संसाधन सहित रणनीतिक महत्व एवं अतिसंवेदनशील सैक्टरो को नियंत्रण मुक्त करना और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश जिसके लिए इनकी सूची तैयार कर ली गयी है। एक ओर नियोजित मजदूरों की न्यूनतम् संख्या बढ़ाकर अधिकांश कारखानों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर करने, तो दूसरी ओर कभी नौकरी पर रखने तथा कभी भी निकालने का हक देने के सम्बन्ध में, श्रम कानूनों में संशोधन, मालिकान के हित में करने जा रही है। हमें इसके विरुद्ध संयुक्त मंच से आन्दोलन की तैयारी की संभावना न सिर्फ देश के पैमाने पर बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर करनी ही होगी।

5.1.6 हर एक संयुक्त आन्दोलन के साथ सीटू यूनियनों को मजदूरों के बीच स्वतंत्र अभियान चलाकर सरकार की इन नीतियों तथा नीतियों के पीछे की राजनीति का पर्दाफास करना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि संयुक्त संघर्ष अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि मजदूर वर्ग में संख्या व गुणवत्ता के लिहाज से बदलाव के लिए सभी संभावनाओं और साधनों का प्रयोग करना है। हमारा लक्ष्य शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करऩा है। सरकार नीतियों एवं उसके पीछे की वर्गीय राजनीति का पर्दाफास करना स्वतंत्र पहल़ का अहम् पहलू है। स्वतंत्र पहल के बिना मजदूरों में उनके ज्वलंत मुद्दों पर एकराय विकसित करना संभव ही नहीं है।

5.1.7 संयुक्त आन्दोलन को सही दिशा में, मजबूत एवं विस्तारित करते हुए उस उँचाई तक ले जाने कि नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सके, उसके लिए जरुरी है कि सीटू और अधिक मजबूत एंव विस्तारित हो। स्वतंत्र गतिविधि और कार्यस्थल से जुड़े विशिष्ट सवालों को नीतियों जोड़कर होने वाले संघर्षों में मजदूरों को शामिल करना सीटू के लिए जरुरी है, ताकि मजदूरों मे जमीनी स्तर पर वर्गीय एकता पैदा की जा सके। और हमारी पहलकदमी की दिशा मजदूरों में राजनैतिक विचारधारात्मक चेतना विकसित करने की होनी चाहिए।

5.1.8 हमारा उद्देश्य आम मजदूरों मे सरकार की जन विरोधी नीतियों और उसकी पक्षधर राजनीति के बारे में जागरुकता पैदा करना है। यह जागरुकता ही संयुक्त आन्दोलन को उस उँचाई तक ले जा सकती है, जहाँ सत्ता को नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो संयुक्त आन्दोलन में गुणात्मक परिवर्तन होगा।

5.2 स्वतंत्र पहल पर प्रस्तावित कार्यक्रम

1. साझा माँग पत्र पर संयुक्त आन्दोलन के साथ ही साथ सीटू से सम्बद्ध यूनियनों व फैड़रेशनों और दोस्ताना व साथी यूनियनों को साझा मुद्दों में किसी विशेष मुद्दे पर स्वतंत्र सघन अभियान चलाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के बहुत ही संवेदनशील सैक्टरों में ठेका मजदूरों का मुद्दा ऐसा है जो मजदूरों के बड़े हिस्से को न सिर्फ आकृष्ट करेगा, बल्कि संगठित एवं असंगठित मजदूरों के आन्दोलन के बीच पुल का काम भी करेगा। अर्थव्यवस्था के बड़े उत्पादक हिस्से में ठेका मजदूरों के लिए सम्बन्धित उद्योग में समान वेतन एवं सुविधाओं की माँग पर मजदूरों को बड़े पैमाने पर लामबन्द करके संघर्ष में उतारा जा सकता है। सीटू को सभी उद्योगों में इस अभियान को लेकर जाना चाहिए चाहे वो निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हों, ताकि संयुक्त आन्दोलन का घ्यान मसले पर केन्द्रित किया जा सके। क्योंकि अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए ठेकेदारी और आऊट सोर्सिंग पूँजीवाद का मुख्य औजार, इस अहम् मुद्दे पर ही संयुक्त संघर्ष को केन्द्रित करने से ही संयुक्त आन्दोलन को एक नई दिशा मिलेगी।

हमारा प्रस्ताव है कि सीटू की सभी इकाईयों को अन्य गतिविधियों के साथ ही साथ ठेका मजदूरों के लिए समान काम के लिए समान वेतन एवं हितलाभ की माँग के लिए अगस्त माह में सघन अभियान चलाऐं। यह अभियान निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाईयों में चलाया जाए और सितम्बर के मध्य में राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन आयोजित किए जाऐं। इस जनरल कौंसिल मीटिंग के तुरन्त बाद सभी राज्यों में इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाऐं।

2. मजदूर आन्दोलन और आम जनता एवं समाज के मध्य तालमेल बैठाने के लिए, जनोपयोगी सेवाओं एवे ऐसी सेवाऐं जिनका ताल्लुक सीधे आम जनता के साथ है, में कार्यरत हमारी यूनियनें व फैडरेशन योजनाओं का लाभ लेने वाली जनता को भी अपने अभियान में शामिल करें। जैसा कि जयपुर में आयोजित कार्यसमिति की बैठक में सीटू ने निर्णय लिया था कि आई. सी.डी.एस. के निजीकरण के खिलाफ ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के आन्दोलन के साथ पूरी सक्रियता से ए.आई.के.एस., ए. आई.ए.डब्ल्यू.यू. और ए.आई.डी. डब्ल्यू.ए. के साथ संयुक्त अभियान विकसित करें। जमीनी स्तर पर हमारे प्रभाव के विस्तार के राजनैतिक महत्व को ध्यान में रखकर अधिकाधिक गम्भीर प्रयासों के साथ जारी रखना होगा।

हमारा प्रस्ताव है कि बिजली के क्षेत्र में भी पहल करनी होगी। बिजली के नियंत्रण मुक्त एवं निजीकरण करने के अभियान में हमारे फैडरेशन इ.इ.एफ.आई. को लाभार्थियों को भी शामिल करना होगा। शुरुआत के लिए सीटू केन्द्र और इ.इ.एफ.आई. किसानो के प्रतिनिधि संगठन के रुप में ए.आई.के.एस. को शामिल करें, और राज्य स्तर पर सीटू, इ.इ.एफ.आई. और ए.आई. के.एस. संयुक्त रुप से राज्य स्तर पर अभियान चलाऐगें। सीटू राज्य कमैटियाँ राज्य स्तर पर इसी प्रकार की पहल करें। जनोपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत यूनियनें इसी प्रकार की पहल करें। नगर निगमों के कर्मचारियों की यूनियनें राज्य/क्षेत्र

के स्तर पर इसी प्रकार की पहल करें।

3. केन्द्र में आयी नयी सरकार के द्वारा नवउदारवादी नीतियों के घातक हमलों के मद्देनजर सीटू को पहले करके सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों को सक्रिय करके, पुर्नगठन के नाम पर विनिवेश के खिलाफ संघर्ष की तैयार करें।

4. सीटू राज्य कमैटियाँ 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को स्कीम कर्मचारियों के लिए लागू करने की माँग को लेकर अभियान चलाऐं। इसके अतिकरक्त अन्य माँगों के लिए ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. और आशा व मिड–डे–मील वर्कर्स की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने अखिल भारतीय माँग दिवस मनाने का फैसला लिया है। सभी राज्य कमेटियाँ इसको प्रभावी ढ़ंग से लागू करना सुनिश्चित करें।

5. सभी राज्य कमेटियाँ अपने राज्य केन्द्रों से अच्छी तैयारी के साथ सीटू के 14वें महाधिवेशन में लिए गए फैसलों को लागू करने की मध्यावधि समीक्षा करें।

6. संगठन के बारे में

6.1.1 हमें पूरी गम्भीरता अपने अन्दर झांककर देखना होगा कि वे बुनियादी सांगठनिक कारण कौन से हैं जो हमारी पूरी सदस्यता तथा आम मजदूरों के बीच स्वयं ही निर्धारित किए आन्दोलनात्मक एवं राजनैतिक–सांगठनिक काम को अन्जाम देने में हमारी कमजोरी और असफलता का कारण बने हुए हैं।

6.1.2 हम ने सीटू के सभी मंचों पर स्थितियाँ का पूरा विश्लेषण किया, और इस बात पर जोर दिया कि हम जिस मुद्दे पर भी दखल दें उसमें चैतन्य होकर वर्गीय दृष्टिकोण साफ नजर आना जरुरी है। मुद्दे को ठीक से जाने और उसे केन्द्रित करते हुए आम मजदूरों के बीच लेकर जाऐं और सुनिश्चित करें कि हमारी गतिविधि संगठन के हर स्तर पर पूरी संजीदगी के साथ चले तथा यूनियन स्तर के नेतष्त्व की समझदारी मजबूत करके अपने सभी सदस्यों एवं आम मजदूर तक पहुँच बना सके।

6.1.3 लेकिन हम इस अवधारणा को अपने मजबूत इलाकों में भी पूरी तरह से लागू नहीं कर सके हैं। अनेकों जगहों पर समझदारी बनयी गयी और काम भी हुआ परन्तु वह सिर्फ औपचारिकता भर ही रहा। क्या हम ने कभी इसकी समीक्षा की है कि हम अपनी समझदारी और उससे निकले काम को अगली श्रेणी के नेतृत्व तक और उसको इसी प्रकार का कदम उठाकर और नीचे ले जाने के लिए तैयार किया है? क्या हम ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी यूनियन/इकाई स्तर की कमेटी तक की है? क्या हम ने पूरी गम्भीरता और मुकम्मल तरीके से समीक्षा की है कि हमारी यूनियन या क्षेत्रीय कमेटी का नेतृत्व अभियान को अपने कितने सदस्यों एवं आम मजदूरों तक अभियान को लेकर गए हैं? इस सम्बन्ध में समीक्षा का अर्थ है, मुकम्मल रुप से आँकलन कि अभियान की गुणवत्ता, उसका प्रभाव और मजदूरों की संख्या जिन तक हम पहुँच सके। हमें यह स्वीकार करना ही चाहिए कि केन्द्र से लेकर नीचे तक अपने काम की समीक्षा के मामले में हम सभी साधारीकरण के परिलक्षण के शिकार हैं, जिसके कारण हम अपने काम का प्रभाव गुणवत्ता और संख्या के लिहाज से आँकलन करने में अक्षम हैं। जिसके परिणाम स्वरुप असफलता और अपने–अपने क्षेत्रों में स्थिति के सामूहिक आँकलन में भारी कमी, जो पिछले चुनावों सहित हमारे हर एक आन्दोलन में नजर आती है।

6.1.4 हमें अपने किसी एक विशिष्ट काम के सदर्भ में अपने अन्दर झांककर देखना होगा। क्या हम सीटू के विभिन्न मंचों पर होने वाली चर्चा और फैसलों के निरुपण के बारे में, अपने जमीनी स्तर के नेताओं/कार्यकर्ताओं तक उचित तरीके से सूचित करते है, और उनके द्वारा मुद्दों को आम मजदूर तक ले जाने के मामले में निगरानी करते हैं? क्या हम ने इस बात

का आँकलन किया कि सीटू की कार्यसमिति, जनरल कौंसिल, राज्य कमैटी, जिला कमैटी या फैडरेशन की मीटिंग में किस पृष्ठभूमि में और कैसे व किस सीमा तक निर्णय लिए गए तथा वह उसी भावना एवं गहराई के साथ निम्नतम् स्तर तक के अपने सदस्यों व कितने साथियों तक पहुँचाया गया? संवाद की इस प्रक्रिया में कितने नेताओं शामिल करने का प्रयास किया तथा कितनों शामिल कर पाए? सीटू केन्द्र ने 14वे महाधिवेशन के बारे में जानकारियाँ साझाा करने के लिए लिखित में बिन्दु सभी राज्य कमैटियों को भेजे थे। केन्द्र में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मात्र कुछ एक राज्य कमेटियों ने ही उन्हे अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करके अपने नेतृत्व में बाँटा ताकि वे आगे जानकारियों को साझा कर सकें। और सीटू की सदस्यता के किस स्तर तक ये जानकारियाँ दी गयी इसकी जाँच, आँकलन और संख्या के बारे में सीटू केन्द्र नहीं कर सका है। हम यह करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। हमारे जैसे संगठन के लिए रिपोर्टिंग करने का अथ सिर्फ फैसलों की जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि लिए गए फैसले की पृष्ठभूमि में राजनैतिक– विचारधारात्मक आधार की समझदारी भी नेतृत्व के हर स्तर तक ले जाना ताकि फैसले को लागू करने की पहल में निचले स्तर तक तथा आम मजदूरों को भी शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया के द्वारा ही हम सही आँकलन और दखल करके जमीनी सच्चाई को जान सकते हैं और उसे जमीनी स्तर तक ले जाकर ही हम सुधार के कदम निश्चित करके तमाम कमियों और खाईयों को पाट सकते हैं।

6.1.5 हम जानते हैं कि हमारे ही द्वारा सुनिश्चित इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाऐं, जो कि हमें अपनी ही पूरी ताकत का उपयोग करने में असफलता का कारण है। इन सभी कमियों की जड़ में संगठन के हर स्तर पर जनवादी कार्यप्रणाली का अभाव है। जनवादी कार्यप्रणाली महज काम करने का तौर तरीका ही नहीं बल्कि यह एक सशक्त उपकरण है जिसके द्वारा समूचे नेतृत्व और निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं आन्दोलन में पूरी तरह शामिल करने की सभी संभावनाऐं खुलकर सामने आ सकती हैं। हमारे काम करने के तरीके में नुक्स तथा सामूहिकता की कमी के चलते हम अभी तक भी अपने निचले स्तर पर कार्यरत साथियों का अपने फैसलों को सम्पूर्णता के साथ लागू करा सकने में असफल ही हैं। यही वजह है कि अपने कार्यक्रम और समझदारी को अपने सभी सदस्यों तक ले जाने में असफल हैं।

6.1.6 इस महत्वपूर्ण पहलू पर 14वें महाधिवेशन में जोर देकर कहा कि "इसे यथार्थ रुप तभी दिया जा सकता है, जब हम संगठन के हर स्तर पर जनवादी कार्यप्रणाली को अधिकाधिक प्रभावी बनाने के लिए, फैसले लेने व लागू करने सहित संगठन की सभी गतिविधियों में अधिकाधिक मजदूरों को शामिल होना सुनिश्चित करें।" साफ है कि इस बारे में हम अभी भी बहुत पिछड़ रहे हैं, इसीलिए मजदूरों का बड़ा हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारी सदस्यता की भी काफी बड़ा हिस्सा वर्ग के रुप में अपनी पहचान नहीं मानता है। सीघे तरीके से कहें तो सीटू अपनी राजनीति में मजदूर वर्ग को लाने में असफल है।

6.1.7 सीटू के 14वें महाधिवेशन में यह भी देखा कि "संगठन/यूनियनों में जनवादी कार्यप्रणाली में लगातार बनी हुई कमजोरी के मूल में हमारी राजनैतिक, विचारधारात्मक समझ की यह कमजोरी है कि जनवादी कार्यप्रणाली ही वह औजार है जिसके द्वारा हम अपने विधान की घोषणा के अनुसार समूचे मजदूर वर्ग के नेता हो सकते हैं। जनवादी कायप्रणाली की यह कमजोरी हमें जमीनी स्तर पर मजदूरों की चेतना का स्तर बढ़ाते हुए, अपनी आन्दोलनात्मक कारवाहियों का विस्तार मजदूरों में नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी ओर संगठन में विभिन्न स्तरों पर जनवादी कार्यप्रणाली की यह कमजोरी, सगठन में सामूहिक कार्यप्रणाली के स्थान पर व्यक्तिवादी नेतृत्व की एक घातक प्रवृत्ति को भी पैदा करती है, जो अन्ततः भ्रष्टाचार के रुप में क्षरण की प्रथाओं को जन्म देकर आम मजदूरों को संगठन से विरक्त ही करती जाती हैं।

6.1.8 हमें हर स्तर पर पूरी गम्भीरता से परखना होगा कि संगठन किस हद तक व्यक्तिवादी संस्कृति का शिकार बना हुआ है। निम्नतम् स्तर तक मजदूरों में वर्गीय चेतना पैदा करके कार्यस्थल तक वर्गीय दृष्टिकोण से काम करने की मजबूती पैदा करने के लिए इन सभी कमजोरियों और गलत तौर तरीकों को समाप्त करना ही होगा। इसके बिना जिन तक नहीं पहुँचा जा सका है पहुँचना और अपने वर्ग का विश्वास जीतना संभव नहीं होगा।

6.1.9 अपने संगठन के हर स्तर पर सीटू कि विभिन्न मंचों पर लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए अधिक चैतन्य होकर ठोस पहल करने में यूनियन स्तर तक की कमेटियों के नेतृत्व को शामिल करना सुनिश्चित करना होगा ताकि वे सांगठनिक पहल को प्रचार–प्रसार अपने सदस्यों व आम मजदूरों तक लेकर जाऐं। इस बुनियादी काम की निगरानी हर स्तर पर वापस रिपोर्ट करने की सांगठनिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है। सीटू केन्द्र, राज्य कमेटियाँ और फैडरेशनों को यह काम पूरी गम्भीरता के साथ इस जनरल कौंसिल मीटिंग से ही लेना है।

6.1.10 नवउदारवादी हमला सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि विचारधारा के क्षेत्र में भी है। पूँजीपति वर्ग आर्थिक हमले के साथ ही साथ, लगातार मीडिया एव अन्य माध्यमों के द्वारा मजदूर वर्ग को सामूहिक पहल और संघर्ष की विचारधारा से भटकाने में पूरा समय देकर वैचारिक हमला भी कर रहा है। समाज में विद्यमान सामन्ती अवशेष और पिछडेपन के कारण जनता इस विघटन और वैचारिक भटकाव का शिकार हो रही है। आर्थिक समस्याओं और सम्बन्धित नीतियों को सिर्फ सत्ता के शासन की कमी बताकर जनता को भमित करना इस साजिकश का हिस्सा है। शासक वर्ग अराजनीतिकीकरण और वैचारिक विभ्रम फैलाने में किसी हद तक सफल हुए हैं, यह अभी हाल के चुनाव परिणामों से साबित होता है। वे विघटनकारी ताकतों का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने में भी सफल हुए हैं। सबसे खतरनाक बात है कि पूँजीपति वर्ग द्वारा पैदा किए इस वैचारिक शून्यता का लाभ हिन्दुत्ववादी ताकतों ने उठाया है। इस जनरल कौंसिल को इस पहलू पर पूरी गम्भीरता से विचार करके, सत्ता में बैठे धुर दक्षिणपन्थी विघटनकारी तत्वों के वैचारिक हमलों का मुकाबला करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाना होगा। मजदूर वर्ग की विचारधारा पर शासक वर्गों के हमलों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा एव वैचारिक अभ्यास का कार्यक्रम अपने जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लिए घनीभूत तरीके से चलाना ही होगा। हमारे अन्य आन्दोलनात्मक कारवाहियों के साथ ही साथ इस काम को जारी रखने और अपने संगठन व ढ़ाँचे को इस दिशा में तैयार करने की पहल करनी है।

6.1.11 आन्ध्र प्रदेश के दो राज्यों में विभाजन और नए तेलंगाना राज्य के जन्म के बाद सीटू संगठन का पुर्नगठन किया गया। आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य कमेटियां बनायी गयी हैं। तदनुसार सभी राज्य स्तरीय यूनियनों को भी बाँट दिया गया है। दोनों राज्य कमेटियाँ अभी हैदराबाद से ही काम कर रही हैं, बाद में आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी को आन्ध्र के इलाके में स्थित कार्यालय में ले जाया जाएगा।

6.2 सदस्यता की स्थिति

6.2.1 वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 के लिए सम्पूर्ण सम्बद्धता शुल्क और वार्षिक विवरण सभी राज्यों से अभी प्राप्त होने बाकी हैं। 13 जून 2014 तक असम, केरल और त्रिपुरा से प्राप्त वार्षिक विवरण के आधार पर ये राज्य अपनी 2011 की सदस्यता पार कर गए हैं, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश 2011 की अपनी आधी सदस्यता तक भी नहीं पहुँचे हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरांचल और प० बंगाल 2011 की सदस्यता से बहुत अधिक पीछे हैं। झारखण्ड की 27 यूनियनों में 2012 की सम्बद्धता/वार्षिक विवरण मात्र एक यूनियन का ही प्राप्त हुआ है। हम समझ सकते हैं कि प० बंगाल में आतंक और हिंसा के कारण बहुत से इलाकों में सदस्यता वसूलना एवं अन्य औपचारिकताऐं पूरी करने में गम्भीर बाधाऐं हैं। लेकिन अन्य राज्यों में क्या हो रहा है? स्थिति यह दर्शाती है कि सदस्यता एकत्र तथा दस्तावेजों के रखरखाव तथा वार्षिक विवरणों को राज्य व केन्द्र में जमा करने में हमारी यूनियनों एवं राज्य नेतृत्व के बीच तालमेल में बहुत सुस्ती है। और इसे महत्वूपर्ण काम की लगातार निगरानी करने राज्यों नेतृत्व की कमजोरी बनी हुई है।

6.2.2 इस समय जून 2014 में हमें 2013 का वार्षिक विवरण और सम्बद्धता शुल्क प्राप्त हो जाने चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा आंशिक रुप से जमा करने के अलावा नहीं हुआ है। राज्य कमेटियों को विशेष प्रयास करके 2012 के वार्षिक विवरण और सम्बद्धता शुल्क जमा करने के साथ ही साथ 2013 के वार्षिक विवरण और सम्बद्धता शुल्क जमा करने के काम में तेजी लानी होगी। ताजा स्थिति के लिए एक विवरण प्रसारित किया गया है।

6.3 सीटू पत्रिकाऐं

6.3.1 सीटू पत्रिकाओं का प्रसार अभी भी एक अस्थायी स्तर पर ही ठहरा हुआ है। जैसा कि राज्यों के व्यक्तिगत ग्राहकी के आँकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्बद्ध यूनियन के सभी पदाधिकारियों के पास भी सीटू की पत्रिकाऐं नहीं पहुँच रही है। 'वर्किंग क्लास' का प्रसार सिर्फ 486 कापियां है जिसमें से 3864 सम्बद्ध यूनियनों तथा मात्र 820 कापी व्यक्तिगत ग्राहकी के तहत हैं। हिन्दीभाषी राज्यों में जहाँ उनकी कोई राज्य स्तरीय पत्रिका नहीं है, में 'सीटू मजदूर' का प्रसार सबसे कम है। 3780 में से 1629 तो अकेले हिमाचल में और 370 प० बंगाल में ही जाती हैं। ''वाईस ऑफ वर्किंग वूमैन'' और ''कामकाजी महिला'' के प्रसार की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है। क्या यही स्थिति जारी रहेगी। सीटू पत्रिकाओं को न सिर्फ अपनी सम्बद्ध यूनियनों व सदस्यों में बल्कि अपनी दोस्ताना यूनियनों व फैडरेशनों के बीच भी लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है, यह काम हमारे राजनैतिक अभियान का अभिन्न हिस्सा है। इन सभी के बीच पत्रिकाओं का प्रसार, ग्राहक बनाने, और लगातार इन्हे पढ़ने के मामले में ढील देने का अर्थ है कि हम अपने राजनैतिक काम में पिछड़ रहे हैं। क्या हम इस काम को भी पूरी गम्भीरता से करेगें?

7. निष्कर्ष

7.1 चुनाव परिणामों से जनता के एक बड़े हिस्से की तमाम आशाओं और अपेक्षाओं के बावजूद भी हमें यह सच्चाई का पता होना ही चाहिए कि अर्थव्यवस्था संकट में है, पूँजीवादी व्यवस्था स्वयं गहरे संकट में फंसी है, और नवउदारवादी निजाम में मेहनतकश जनता पर हमले अवश्यसंभावी हैं। सत्ता में बैठे नवउदारवादी समर्थक राजनैतिक दलों के लिए बहुत आरामदायक स्थिति नहीं होगी, और इसका बुरा असर आम जनता पर भी पड़ेगा तथा समय बीतने के साथ जनता में असंतोष भी बढ़ेगा। नवउदारवादी नीतियों से जन्मे संकट के चलते जनता के अधिकारों और जीविका पर हमले जरुर होगें। हमें पहल करके, जब भी जनता में असंतोष बढ़ना शुरु होता है तो मेहनतकशों और समूचे मजदूरवर्ग में अभियान, प्रतिरोध और संघर्षों के लिए तैयार रहना ही होगा।

7.2 इसमें कोई शक नहीं है कि इन चुनाव परिणामों से बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसके कारण न तो हतोत्साहित होकर बैठा जा सकता है और ना ही मैदान छोड़ा जा सकता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि दक्षिणपन्थी कह सकते हैं कि अटूट वामपन्थी विकल्प का संदेश जनता के बीच नहीं जा सकता है, परन्तु हमें पहले करके सभी मजदूरों के बीच जाकर संदेश ले जाना ही होगा।

7.3 वामपन्थी वैकल्पिक नीति समय के साथ परखी हुई है। यदि यह मेहनतकशों तक उनके रोजमर्रा के अनुभवों के साथ जोड़कर पहुँचे तो वो निश्चित रुप से प्रतिक्रिया करेगें। यही तो हमारा वर्गीय काम है जो दक्षिणपन्थी के जन विरोधी काम और हमलों का मुकाबला कर सकता है। मजदूरवर्ग के वर्गीय लडाकू दस्ते के रुप में सीटू को यह जिम्मेदारी निभाते हुए सभी मेहनतकशों के बीच जाना ही होगा।

7.4 देश का मजदूर आन्दोलन एक संयुक्त मंच के रुप में विकसित हो चुका है और पिछले 5 वर्ष से अपने 10 सूत्रीय माँग–पत्र के लिए संघर्ष कर रहा है, जो पूरी तरह से वामपन्थी विकल्प के अनुरुप ही है। हमें उसको और अधिक विस्तारित एवं मजबूत करते हुए आगे लेकर जाना है। यही हमारा महत्वपूर्ण काम है। अपने पिछले अनुभवों से सीख लेकर गम्भीर पहल करके इस एकता और संघर्ष को उँचाईयों पर लेजाना है। आने वाले दिनें में वर्तमान सत्ता से मजदूरों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आने वाले हमलों और खतरों के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध तैयार करना ही होगा। और नवउदारवादी नीतियों का खुलासा करते हुए आम मजदूरों को एकताबद्ध करने के लिए सीटू को अपने स्वतंत्र मंच से पहल करनी होगी।

7.5 हमें साम्प्रदायिक–फासीवादी सरकार के दक्षिणपन्थी खतरों का मुकाबला करने के लिए कार्यस्थल तक पूरी समझदारी के साथ तैयार कराना होगा। यदि हम जनता तक पहुँचेगें तो वह हमारा साथ अवश्य देगी। जन विरोधी नवउदारवादी नीतियों के विकल्प के साथ जिन तक हमारी पहुँच नहीं है उन तक पहुँच बनाने से यह संभव भी है। हमें इसके लिए काम करना ही होगा। इसके लिए यह जरुरी है कि यह काम हमारी चेतना का अटूट हिस्सा बने। हम यह कर भी सकते हैं और कि हम निश्चित रुप से जीतेगें।

मज़दूर एकता जिन्दाबाद
सी.आई.टी.यू. जिन्दाबाद
दुनिया भर के मेहनतकशों एक हो

तपन सेन
महासचिव

✱✱✱✱✱✱✱✱

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

बेल्लारी, कर्नाटक

11–14 जुलाई, 2014

सीटू वर्किंग कमेटी की जयपुर बैठक के बाद की गतिविधियों की रिपोर्ट

वर्किंग कमेटी की अगस्त 2013 में जयपुर में हुई बैठक के प्रमुख आह्वानों के अमल पर आत्मालोचनात्मक और आलोचनात्मक चर्चा महासचिव की रिपोर्ट में की गई है।

इस दौरान, राज्य समितियों की ओर से रिपोर्ट भेजने के मामले में कुछ सुधार हुआ है। तथापि, अभी भी कुछ राज्य समितियां ऐसी हैं जो अपनी गतिविधियों की कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजती हैं। ऐसा भी है कि उन राज्य समितियों की ओर से , जो आमतौर पर रिपोर्ट भेज देती हैं, प्रमुख और महत्वपूर्ण संघर्षों की समय पर रिपोर्ट नहीं भेजी गयीं। इसी प्रकार, आम अड़तालों जैसे अहम आह्वानों की रिपोर्ट भेजने के मामले में हालांकि सुधार हुआ है परन्तु ज्यादातर राज्य समितियाँ, मई दिवस, सीटू स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की रिपोर्ट तुरन्त नहीं भेजती हैं।

सीटू सचिव मंडल ने 14–15 जून को अपनी बैठक में समय पर रिपोर्ट भेजने के पहलू, खासतौर पर किसी राज्य स्तरीय अभियान/संघर्ष आदि के बाद और राज्य समिति बैठक के बाद समय पर रिपोर्ट भेजने के महत्व पर पुनः जोर दिया है। हर महीने की 15 तारीख तक नियमित रिपोर्ट, फोटो आदि भेजने के साथ ही राज्य समिति बैठक के बाद तुरन्त रिपोर्ट भेजने और अखिल भारतीय केन्द्र के साथ संपर्क बनाये रखने के लिए राज्य समिति के एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिये। इससे हमारे मासिक मुखपत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित करने में भी मदद मिलेगी।

जयपुर में सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद के दौर में दो प्रमुख घटनायें घटी हैं। इनमें से एक 12 दिसम्बर, 2014 का संसद मार्च और दूसरी 16वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार की है जो नव–उदार नीतियों के मजबूत प्रवक्ता और वाहक काँग्रेस और भाजपा को हराने और गरीबों की पक्षधर वैकल्पिक नीतियों की पैरोकार वामपंथी पार्टियों को समर्थन करने पर आधरित था। इसके अतितिक्त, इस दौरान सीटू और उसकी संबद्ध यूनियनों के नेतृत्व में अधिकतर राज्यों में स्थानीय मुद्दों पर बहुत सारे अभियान व संघर्ष हुए हैं; इनमें आंध्रप्रदेश भी शामिल है जहाँ राज्य का विभाजन हुआ और गंभीर राजनीतिक उठा–पटक देखने में आयी।

चुनाव के सघन प्रचार के बीच हमारी सभी राज्य समितियों ने मई दिवस मनाया। इस अवसर पर स्वतन्त्र व संयुक्त रैलियां आयोजित की गईं। चूकि चुनाव आयोग ने इस दिन जुलूस निकालने की इज़ाजत दी थी इसलिए कुछ राज्यों में मई दिवस को चुनाव अभियान के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिशें की गईं।

सीटू के स्थापना दिवस को सीटू केन्द्र के साथ–साथ देशभर में मनाया गया।

सीटू की लगभग सभी राज्य कमेटियों ने कॉमरेड ज्योति बसु की जन्मशती मनाने के कार्यक्रम किये। केरल राज्य समिति ने इस सिलसिले में कोझिकोड़, एरनाकुलम और थिरूअनंतपुरम में तीन सेमिनार आयोजित करने का फैसला किया। इसके अलावा अक्टूबर–नवम्बर में राज्य के सभी जिलों में सेमिनार, रैलियां आयोजित करने की योजना भी बनाई गई थी। राज्य समिति ने इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित करने का भी फैसला लिया।

पश्चिम बंगाल राज्य समिति ने कॉमरेड ज्योति बसु की जन्मशती को भली भांति मनाने का फैसला किया। जन्मशती की शुरूआत के दिन 8 जुलाई को राज्य में सीटू के सभी केन्द्रों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यह भी तय किया गया कि जाने–माने ट्रेड यूनियन और राजनीतिक नेताओं के लेखों के संकलन वाली एक पुस्तक भी प्रकाशित की जायेगी।

आंध्रप्रदेश में कॉ0 ज्योति बसु की जन्मशती की शुरूआत करते हुए 10 अगस्त को सीटू की आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी द्वारा हैदराबाद में एक सेमिनार आयोजित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हुए इस वर्ष सीटू ने सभी पहलुओं में समानता, सभी कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हर तरह की हिंसा को रेकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांगो पर अपने आयोजनों को केन्द्रित किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सीटू की लगभग सभी राज्य समितियों द्वारा मनाया गया लेकिन सीटू की राज्य समितियों की ओर से सभी जगह एक जैसी पहल कदमी नही रही और सभी राज्य समितियों से रिपोर्ट भी नहीं प्राप्त हुईं। इस दिन बैठकें, सेमिनार, कन्वेंशन, प्रदर्शन आदि का आयोजन किया गया। कुछ राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, बैंक व बीमा कर्मियों, शिक्षकों आदि के बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों को भी कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए प्रयास किये गये। कई राज्यों में इस दिन को एडवा के साथ संयुक्त रूप से मनाया गया।

महासचिव की रिपोर्ट में, चुनावों में हमारी भूमिका की विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ हम अपनी चर्चा को राज्य समितियों द्वारा भेजी गईं रिपोर्टों पर आधरित विभिन्न राज्यों में हुईं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों तक सीमित रखेंगे।

12 दिसम्बर का संसद मार्च और संबंधित कार्यक्रम

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर हुए 12 दिसम्बर के संसद मार्च में देशभर से लगभग 2.5 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। सीटू और एटक तथा उनसे जुड़े फेडरेशनों की इसमें प्रमुख लामबंदी रही। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अन्य घटकों की इसमें टोकन उपस्थिति रही। राज्यों और विभिन्न फेडरेशनों से प्राप्त की गईं रिपोर्टों के हिसाब से सीटू ने इसमें 72609 मजदूरों की लामबंदी की। इसके अलावा हमसे जुड़ी स्वतंत्र फेडरेशनों जैसे, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज, बी ई एफ आई, ए आई आई ई ए और बी एस एल इ यू ने लगभग 15,865 कर्मियों को लामबंद किया।

संसद मार्च में हिस्सा लेने वालों के ठहरने के लिए 9 दिसम्बर, 2013 से रामलीला मैदान में एक शिविर लगाया गया था।

उन राज्यों में, जहाँ से मजदूरों की दिल्ली में लामबंदी नही हो सकी थी, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने वहाँ उसी दिन राज्य/जिला स्त्ररीय लामबंदी करने का भी फैसला लिया था। केन्द्र में प्राप्त हुई रिपोर्टों के मुताबिक केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में मजदूरों की विशाल लामबंदिया हुईं। केरल में 14 केन्द्रों में 1,11,800 मजदूरों ने रैलियों/प्रदर्शनों में शिरकत की। कोल्लम, इडुक्की व कन्नूर को छोड़कर इंटक सभी जिलों में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल में 13 जिलों में आयोजित हुए प्रदर्शनों/जुलूसों में कुल 59,900 मजदूरों ने भाग लिया। त्रिपुरा में, 74 केन्द्रों में 34,585 मजदूरों ने शिरकत की। तमिलनाडु में भी सभी जिलों में रैलियां आयोजित हुईं जिनकी विस्तृत जानकारी नहीं मिली। झारखंड में भी जमशेदपुर में एक संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किया गया। अन्य राज्यों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

वर्किंग कमेटी द्वारा मजदूरों व जनता के व्यापक तबकों की प्रमुख मांगों को सामने लाते हुए उनके बीच पहुँचने के लिए स्वतंत्र व संयुक्त दोनों ही तरह से सघन अभियान के महत्व पर ज़ोर दिया गया था। सभी राज्य समितियों से इस अभियान की विस्तृत रिपोर्ट भेजने का भी आग्रह किया गया था।

हालांकि, ज्यादातर राज्य समितियों ने व्यापक अभियान की तैयारियां कीं तथापि इस अनुरोध पर ज्यादा राज्यों ने ध्यान नहीं दिया। केन्द्र में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली राज्य समिति ने पोस्टरों व दीवार लेखन के अलावा 2.5 लाख पर्चे व 16,000 स्टिकर छपवाये; जिलों में गेट/गली/मोहल्ला बैंठके की गयीं; तमिलनाडु राज्य समिति द्वारा जिला/उद्योग स्तर के अभियान के साथ 57,500 पर्चे/नोटिस 4600 पोस्टर व अन्य सामग्री छपवाई गई; उत्तरप्रदेश में 8 जिला स्तरीय बैठकें की गयीं; 8000 पर्चे व 10,000 पोस्टर वितरित किये गये; यू पी एम एस आर ए ने 2000 पोस्टर छपवाये। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रेदश व कुछ अन्य राज्यों में भी यद्यपि राज्यव्यापी अभियान आयोजित किये गये लेकिन उनसे कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयीं। परिणाम स्वरूप देशभर में मजदूरों व जनता के बीच हमारे अभियान की पहुंच और दायरे के बारे में समुचित आकलन नही किया जा सकता है।

अन्य गतिविधियां

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय कन्वेंशन

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की दसवी राष्ट्रीय कन्वेंशन 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2013 को पुरी, उड़ीसा में आयोजित की गई। इस कन्वेंशन में 20 राज्यों की 262 कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। वे इस्पात, कोयला, बिजली, आईटी, बीमा, बैंकों, राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभागों, बी.एस.एन.एल., सार्वजनिक परिवहन तथा आटो ड्राइवरों जैसे निजी परिवहन, निर्माण, ईंट भट्टा, हथकरघा, सिले– सिलाए वस्त्र, घरों में होने वाले कामों और नारियल जटा, काजू, मछलीपालन, बागान तथा बीड़ी जैसे परंपरागत उद्योगों, एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मिल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसी केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे विभिन्न

किस्म के उद्योगों तथा क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं और घरेलू मजदूरों, निजी अस्पतालों के कर्मचारियों, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों और फेरीवालों आदि का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जयपुर सीटू कार्यसमिति बैठक के निर्णयानुसार सीटू की 13 राज्य कमेटियों के अध्यक्षों, महासचिवों और चार अन्य राज्य कमेटियों के कामकाजी महिलाओं के प्रभारी पदाधिकारियों ने भी इस कन्वेंशन में भाग लिया।

इस अवसर पर 29 सितम्बर को एक रैली का आयोजन किया गया। राज्य भर से करीब 8000 महिलाओं ने हजारों पुरूष मजदूरों के साथ रैली में भाग लिया।

संयोजिका की रिपोर्ट कन्वेंशन में सर्वसम्मति से पारित कर दी गई जिसके साथ कामकाजी महिलाओं के बीच चलाए जाने वाले अभियान के आधार पर एक मांगपत्र भी पारित किया गया। कन्वेंशन में निर्णय लिया गया कि ये मांगे मुख्यतः समान वेतन, मातृत्व लाभ तथा पालनाघरों, तमाम संस्थानों तथा जिलों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कमेटियों के गठन,महिलाओं के लिए अलग शौचालयों के प्रावधान और तमाम कर्मस्थलों में आराम कक्षों की व्यवस्था और कम से कम 10,000 रू0 महीना न्यूनतम वेतन जैसी मांगों को को लेकर अगले तीन महीने तक जर्बदस्त देशव्यापी अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। कामकाजी महिलाओं के बीच सीटू के काम को मजबूत करने के लिए कुछ संगठनात्मक कार्यों की भी सिफारिशें की गई।

कन्वेंशन ने कामकाजी महिलाओं की 34 सदस्यीय अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया गया। उड़ीसा सीटू राज्य कमेटी द्वारा कन्वेंशन के शानदार आयोजन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई।

कामकाजी महिलाओं के बीच सीटू के काम को 29–30 जनवरी को बी टी रणदिवे भवन नयी दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बारह राज्यों से आए सीटू के 28 नेताओं तथा केन्द्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाग लेने वालों में 17 महिलाएं भी थीं। सीटू सचिवमंडल ने कार्यशाला की समीक्षा की और और कार्यशाला में प्रस्तावित कार्यों का समर्थन किया। यह फैसला किया गया कि राज्यों में महिला उप समितियों का गठन किया जाए जो कामकाजी महिलाओं के बीच सीटू के कामों की देख रेख करें; इसके लिए एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाए; जिन यूनियनों में महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय है, उन में महिला उप समितियों का गठन किया जाए; सभी राज्यों तथा सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन किया जाए; इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रगति की समीक्षा समय–समय पर की जाए।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन की कार्यसमिति की बैठक 30 जनवरी 2014 को हुई। बैठक में संयुक्त संघर्ष को जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में अपने सदस्यों का आह्वान किया गया कि कांग्रेस व भाजपा को हराने और वामपंथी दलों के समर्थन में अभियान चलाकर सदस्य उसमें सक्रियता से भाग लेने का निर्णय लिया। सभी राज्य कमेटियों को अनुवाद करके बांटने के लिए चुनाव अभियान के पर्चे का प्रतिरूप भेजा गया था। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट व नॉर्थ ज़ोनल कमेटियों की बैठकें आयोजित की गईं। मुम्बई में बेस्ट (बीईएसटी) तथा हरियाणा रोडवेज़ के हड़ताली कर्मचारियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई। लगभग 1000 ऑटो वर्कर्स, मालिकों व सर्विस प्रोवाईडर्स ने पटना में हुई एक कन्वेंशन में भाग लिया।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आइफा)

आइफा के आह्वान पर 10 जुलाई 2013 को देशभर के आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 'काला दिवस' मनाया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के कर्मचारियों ने इस दिन काले कपड़े पहनकर, काले झंडे हाथ में लेकर, काले बैज पहनकर और बहुत से स्थानों पर अपने चेहरों को काले रंग से पोतकर प्रदर्शनों, धरनों, रैलियों इत्यादि में भाग लिया। केरल में यह कार्यक्रम 19 जुलाई को आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश में यूनियन ने 8 से 10 जुलाई तक तीन दिन की हड़ताल रखी। आईसीडीएस मिशन के तहत आईसीडीएस का निजीकरण करने के विरोध में महिला एवं बाल विकास मंत्री के पुतले जलाए गए। 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने, न्यूनतम वेतन, पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देने, कर्मचारी की मान्यता तथा संगठन का अधिकार जैसी मांगें उठाई गईं। बहुत से राज्यों कार्यक्रम को रोकने के इरादे से प्रशासन व पुलिस की कोशिशों को नाकाम करते हुए 18 राज्यों के 210 से अधिक जिलों में दो लाख सात हजार आंगनवाड़ी कर्मचारी इस दिन सड़कों पर उतरे। कर्नाटक में 3 स्थानों पर पुलिस द्वारा लाठियां चलाई गईं। कर्नाटक में लगभग तीन स्थानों पर, पंजाब में दो स्थानों तथा छत्तीसगढ़ व हरियाणा में आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश में विभिन्न जिलों में कम से कम पांच हजार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। 'काला दिवस' के अभियान के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं में 10,000 पर्चे व 50000 हिन्दी पुस्तिकाएं बांटी गईं।

अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन कर्मचारी समन्वय समिति

45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने, 12 महीने वेतन मिलने, छः माह का सवेतन मातृत्व लाभ, सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा की मांग करते हुए 13 फरवरी 2014 को संसद के समीप धरना आयोजित किया गया जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओदिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड – 9 राज्यों से लगभग 2000 मध्याह्न भोजन कर्मचारियों ने भाग लिया। इन्हीं मांगों पर 10 – 17 फरवरी को राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किए गए।

राज्यों की रिपोर्ट अंग्रेजी दस्तावेज़ में दी गई है।

****

ACCOUNTS FOR THE YEAR 31st MARCH 2013

AUDITORS' REPORT

We have examined the Balance Sheet of Centre of Indian Trade Unions as at 31 st March, 2013 and the Income & Expenditure account and Receipt and Payment account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said institution.

We have obtained all the information and explanations and in our opinion, proper books of account have been maintained by the above named institution so far as appears from our examination of the books subject to the notes on accounts.

In our opinion and to the best of our knowledge, and according to information given to us, the said accounts read with the Notes on Accounts give a true and fair view:-

1.In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named institution as at 31.03.2013 and

2.In the case of the income and expenditure account, of the excess of income over expenditure for the year ending 31-03-2013

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2013

LIABILITIES	RUPEES	RUPEES		ASSETS	RUPEES	RUPEES
GENERAL FUND				**FIXED ASSETS**		2,282,527
Opening Balance	30,942,085			(As per Schedule attached)		
Add: Excess of Income	2,502,041	33,444,126				
Expenditure Account				**INVESTMENTS**		
				Fixed Deposits with Banks		41,000,000
CURRENT LIABILITIES &						
PROVISIONS				**CURRENT ASSETS,**		
a) Current Liabilities				**LOANS AND ADVANCES**		
Audit Fee Paable	83,754					
SPECIAL FUND				a) Current Assets		
Tsunami Victim Relief Fund	3,984,812			Balance with Banks	6,885,640	
Com.P.R.Fund	18,053,576			Cash in hand	23,464	
ASHA Workers Fund	42,460			Bank Gurantee	12,114	6,921,218
Mid Day Meal Fund	24,764			b) Loans & advances		
Bihar Flood Relief Fund	66,550			(Advances recoverable in		6,237,751
Staff Payable Welfare Fund	122,500			cash or kind for which value		
Int.Coal Mines Workers Fun	618,954			to be received.)		
		22,997,370				
		56,441,496				**56,441,496**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- Sd/- Sd/-

(PRESIDENT (SECRETARY) (TREASURER)

Place : New Delhi

Dated : 24/09/2013

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2013

EXPENDITURE	RUPEES	RUPEES		INCOME	RUPEES	RUPEES
Communication Exp.		124,917		Sale of Magazines		615,972
Magazine Expenses		1,158,408		Publication A/c		24,542
Meeting, Rally, & Seminar Expenses		1,522,861		Affiliation Fee		5,820,010
Misc.Exp.		24,584		Bank Interest		2,741,727
Travelling & Convenyance Exp.		343,429		Donation		306,357
Vehical Expenses		127,664		Misc.Receipts		5,485
14th Conference Exp.		42,789		Interest on FDR		639,809
Gzb.Flats Developments Exp.		437,750		Mahapadav Nov-12 Receipts		471,925
Bank Charges		3,987		WFTU		134,335
Building Maintenance		48,663				
Electricity & Water Expenses		632,518				
Com.P.Rammuty T.U.School Exp.		21,000				
Education Allowance		19,500				
Kamkaji Mahila Binding		2,425				
Kamkaji Mahila Misc.Exp.		30				
Kamkaji Mahila Postage Exp.		8,438				
Kamkaji Mahila Printing Exp.		35,640				
Medical Exp.		172,369				
NP, Period.& Books Exp.		19,278				
Office Upkeep Expenses		16,139				
Publication Expenses		49453				
Relief & Subsidy		47,000				
Rent, Rate & Tax		16,125				
Repair & Maintenance-Elec.		5,716				
Service & Maintenance		100,312				
Staff Welfare Fund		7,200				
Stationery & Printing		143,594				
Audit Fees		28,090				
WFTU Affiliation Fees		126,900				
Depreciation		148,553				
Tea & Tiffin Exp.		54,553				
Wages & Allowances		1,718,000				
Bad Debt		985,436				
Excess of Income over Expenditure tfd.to Balance Sheet		2,502,041				
		10,695,362				10,760,162

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- Sd/- Sd/-

(PRESIDENT (SECRETARY) (TREASURER)

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

Place : New Delhi

Dated : 27/09/2013

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2013

RECEIPTS	RUPEES	RUPEES		PAYMENTS	RUPEES	RUPEES
OPENING BALANCE				Communication Exp.		124,917
Cash in hand	98,908			Magazine Exp.		1,158,408
Cash at Banks	7,447,916	7,546,824		Meeting, Rally & Seminar Exp.		1,522,861
Sale of Magazines		615,972		Misc.Exp.		24,584
Publication A/c		24,542		Travellingn & Convenyance Exp.		343,429
Affiliation Fee		5,820,010		Vehicles Exp.		127,664
Bank Interest		2,741,727		14th Conference Exp.		42,789
Donation		306,357		Gzb.Flats Devlopement Exp.		437,750
Miscellaneous Receipts		5,485		Bank Charges		3,987
Interest on FDR		639,809		Building Repair& Maintenance		48,663
Mahapadav Nov-12 Recipts		471,925		Electricity & Water Exp.		632,518
WFTU		134,335		Com.P.Rammuty T.U.School Exp.		21,000
FDRs		11,000,000		Education Allowance		19,500
Com.P.R.Fund		1,610,847		Kamkaji Mahila Binding		2,425
ASHA Workers Fund		19,000		Kamkaji Mahila Misc.Exp.		30
Mid Day Meal Workers Fund		10,964		Kamkaji Mahila Postage Exp.		8,438
Other Loan and Advances		121,193		Kamkaji Mahila Printing Exp		35,640
				Medical Expenses		172,369
				NP, Period. & Books Exp.		19,278
				Office Upkeep Expenses		16,139
				Publication Expenses		49,453
				Relief & Subsidy		47,000
				Rent, Rate & Tax		16125
				Repair & Maintenance-Electrical		5,716
				Service & Maintenance		100,312
				Staff Welfare Fund		72,000
				Stationery & Printing		143,594
				WFTU Affiliation Fees		126,900
				Tea & Tiffin		54,553
				Wages & Allowances		1,718,000
				Fixed Assets		118,408
				Investment		16,000,000
				Bad Debts		945,436
				CLOSING BALANCE		
				Cash in hand	23,464.00	
				Cash at Banks	6,885,640.00	6,909,104
		31,068,990				**31,068,990**

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- Sd/- Sd/-

(PRESIDENT (SECRETARY) (TREASURER)

Place : New Delhi

Dated : 24/09/2013

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

STATEMENT SHOWING STATEWISE MEMBERSHIP AS PER ANNUAL RETURNS RECEIVED TILL 01/07/2014

State	Unions Submitting Returns			Position of membership according to Annual Returns					
	2011	2012	2013	2011	Female	2012	Female	2013	Female
Andaman & Nicobar	9	0	0	3443	*183*	0	*0*	0	*0*
Andhra Pradesh	702	637	0	665459	*207548*	522217	*188220*	0	*0*
Assam	82	75	1	106731	*54298*	106996	*61534*	1029	*0*
Bihar	22	7	1	48357	*17365*	27230	*16204*	8132	*52*
Delhi	77	68	4	60315	*6757*	42513	*1906*	168	*14*
Goa	6	0	0	443	*3*	0	*0*	0	*0*
Gujarat	24	0	0	24974	*10172*	0	*0*	0	*0*
Himachal Pradesh	55	49	10	44019	*23413*	41965	*21161*	36156	*20381*
Haryana	49	34	14	106569	*36269*	99106	*36680*	87004	*26256*
Jammu & Kashmir	8	7	1	7102	*767*	6296	*438*	1300	*0*
Karnataka	154	137	43	229227	*110972*	223548	*123666*	29095	*7286*
Kerala	851	825	281	1512781	*529378*	1547994	*533217*	571675	*209567*
Madhya Pradesh	91	48	0	57226	*24492*	39179	*22702*	0	*0*
Maharashtra	133	95	11	154513	*78085*	133913	*65483*	11382	*4714*
Orissa	81	53	5	174557	*62726*	57646	*8427*	620	*135*
Punjab	69	42	16	135511	*40802*	109893	*27730*	98460	*31416*
Rajasthan	108	81	35	58259	*3947*	42181	*2129*	14213	*671*
Tamilnadu	606	598	187	547308	*154320*	522172	*153381*	166219	*49568*
Tripura	39	38	0	197204	*76311*	203848	*76965*	0	*0*
Uttar Pradesh	85	50	0	30235	*960*	19194	*527*	0	*0*
West Bengal	1195	1015	434	1423132	*354796*	1182310	*310582*	650898	*228180*
Uttarakhand	42	36	31	45703	*13618*	37006	*8857*	29497	*7207*
Chhatisgarh	14	7	1	21274	*3471*	17027	*1103*	12712	*395*
Jharkhand	27	13	0	146304	*40529*	122689	*38560*	0	*0*
Manipur	0	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*
Mizoram	0	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*
Total	**4529**	**3915**	**1075**	**5800646**	**1851182**	**5104923**	**1699472**	**1718560**	**585842**

Year	No. of Unions	Membership	Year	No. of Unions	Membership
1983	1854	1890993	2000	3771	3126943(646678)
1984	2005	1575655	2001	3787	3150673(600407)
1985	1717	1716457(132536)	2002	4168	3463920(679712)
1986	2412	1844273(209348)	2003	3913	3333568(636718)
1987	2350	1680884(206482)	2004	3985	3544622(728891)
1988	2618	1919280(264507)	2005	4088	3990685 (898239)
1989	3114	2425000(247388)	2006	4764	4133893 (916292)
1990	2934	2095550(245060)	2007	4606	4781681(1150108)
1991	2783	2088218(291228)	2008	4485	5173363(1292838)
1992	3343	2381012(321620)	2009	4737	5015260 (1357910)
1993	3156	2371405(306344)	2010	4528	5224207(1552748)
1994	3198	2470131(261980)			
1995	3523	2784050(358188)			
1996	3645	2805127(435285)			
1997	3804	2917200(506097)			
1998	3502	2881478(483373)			
1999	3929	3296808(550583)			

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

P RAMAMURTY FUND (STATES)

SL	NAME OF STATE	MEMBERSHIP-2008	P R FUND QUOTA	RECEIVED FUND	FUND DUES	RECD.AFTER CONF.
1	Andaman	2992	14960.00	5600.00	9360.00	
2	AP	444695	2223475.00	2346399.00		
3	Assam	71991	359955.00	15000.00	344955.00	
4	Bihar	24762	123810.00	25560.00	98250.00	
5	Chattisgarh	21712	108560.00	59897.00	48663.00	
6	Delhi	36877	184385.00	56687.00	127698.00	
7	Goa	677	3385.00	1206.00	2179.00	
8	Gujarat	14849	74245.00	1000.00	73245.00	
9	Haryana	67255	336275.00	140030.00	196245.00	30990.00
10	HP	40523	202615.00	20000.00	182615.00	
11	J & K	4372	21860.00	1240.00	20620.00	
12	Jharkhand	99503	497515.00	6500.00	491015.00	
13	Karnataka	161580	807900.00	684628.00	123272.00	62863.00
14	Kerala	1269686	6348430.00	5240255.00	1108175.00	524181.00
15	MP	31516	157580.00	74274.00	83306.00	
16	Maharashtra	113732	568660.00	520000.00	48660.00	
17	Orissa	108780	543900.00	54251.00	489649.00	
18	Punjab	79000	395000.00	136247.00	258753.00	
19	Rajasthan	41432	207160.00	56250.00	150910.00	29250.00
20	Tamil Nadu	522146	2610730.00	1221150.00	1389580.00	400000.00
21	Tripura	161049	805245.00	310000.00	495245.00	
22	UP	32432	162160.00	42994.00	119166.00	
23	Uttarakhand	20102	100510.00	21500.00	79010.00	
24	West Bengal	1799140	8995700.00	2000000.00	7995700.00	
25	Manipur					
26	Mizoram	2560	12800.00		12800.00	
	TOTAL	5173363	25866815	13040668	13949071	1047284
	As on DT.1-7-2014					

State-wise Circulation of CITU Journals
AS ON July 2014

States	The Working Class – Affiliation 2012	The Working Class – Jul-14	CITU Mazdoor – Affiliation 2012	CITU Mazdoor – Jan-14	The Voice of the Working Woman – Jul-14	Kamkaji Mahila – Apr-Jun 2014
Andaman	0	9	0			
Andhra Pradesh	637	881	637	1	440	
Arunachal						
Assam	75	116	75	14	33	
Bihar	7	4	7	55	6	
Chhatisgarh	7	20	7	448		110
Delhi	68	77	68	145	108	100
Goa		7				
Gujarat		1		24	1	
Haryana	34	2	34	234	3	1
Himachal Pradesh	49	2	49	353	1	
Jammu & Kashmir	7	6	7	54	1	
Jharkhand	13	3	13	84	2	5
Kerala	825	926	825		873	
Karnataka	137	274	137		77	10
Sikkim						
Maharashtra	95	72	95	164	41	151
Madhya Pradesh	48	12	48	391	1	200
Manipur						
Meghalaya		1				
Mizoram						
Nagaland						
Orissa	53	159	53	6	1	
Punjab	42	5	42	82	4	785
Puducherry					2	
Rajasthan	68	5	68	210		
Sikkim						
Tamilnadu	505	687	505		754	
Tripura	38	44	38		140	
Uttar Pradesh	50	24	50	480	4	10
Uttarakhand	36	1	36	100		
West Bengal	1015	1473	1015	364	140	
TOTAL	**3809**	**4811**	**3809**	**3209**	**2632**	***1372**

* In addition to this around 500 copies are taken by Haryana and MP Anganwadi and Asha unions regularly and paid issue by issue

Centre of Indian Trade Unions

State wise quota and Participation in the 'March to Parliament'

12-Dec-13

Sl No	Name of the state	Participation on 23-Feb-11	Quota for 12-Dec-13	Participation on 12-Dec-13
1	AP	1500	4000	1500
2	Assam	550	1000	840
3	Bihar	3000	5000	1700
4	Chattisgarh	513	2000	555
5	Delhi	4900	10000	6308
6	Gujarat	1600	1000	1100
7	Haryana	12547	15000	10000
8	HP	1000	1000	603
9	J & K	0	300	20
10	Jharkhand	1000	7000	1200
11	Karnataka	2597	5000	500
12	Kerala	1500	2500	2500
13	MP	5160	15000	5600
14	Maharashtra	8650	6000	7000
15	Odisha	3500	10000	1400
16	Punjab	15000	25000	20000
17	Rajasthan	4500	10000	3000
18	Tamil Nadu	4000	3000	1800
19	Tripura	47	500	70
20	UP	3305	5000	2813
22	Uttarakhand	1065	500	1300
23	West Bengal	2000	2500	2800
		77934	131300	72609

Mobilisation of Fraternal Unions

AIIEA	**2000**
BEFI	**465**
State Govt employees	**8000**
Central Government Employees	**4300 +**
BSNL	**1100**
Total	**15,865**

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

बेल्लारी, कर्नाटक

11–14 जुलाई, 2014

NAME OF THE STATE	**Time allocated (In Minutes)**
Andaman & Nicobar	10
Andhra Pradesh	25
Assam	20
Bihar	20
Chhattisgarh	20
Delhi	20
Goa	10
Gujarat	10
Jammu & Kashmir	10
Jharkhand	20
Haryana	20
Himachal Pradesh	20
Karnataka	30
Kerala	50
Madhya Pradesh	20
Maharashtra	20
Manipur	10
Orissa	20
Punjab	20
Rajasthan	20
Tamil Nadu	40
Telengana	25
Tripura	30
Uttar Pradesh	20
Uttarakhand	20
West Bengal	60
Industrial Federations/co ordination committees*	150
CITU Centre	15
Total	**765**

**(Anganwadi, Beedi, Coal, Construction, Electricity, Fisheries, LIC Agents, Oil, Plantation, Road Transport, Steel, Water Transport, Mid Day Meal, ASHA, Working Women)*